सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh
RNI No :- DELHI/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023
www.newsparivahan.com
परिवहन विशेष
वर्ष 02, अंक 179, नई दिल्ली । रविवार, 08 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8
देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार
जीवन साइकिल की सवारी करने जैसा है, संतुलन बनाये रखने के लिए चलते रहना जरूरी है।

03 रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगाना अनुचित, मोदी सरकार वापस ले प्रस्ताव
06 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल को अनलॉक
08 सांसद मानस रंजन मंगराज ने सुजीत को आस्था का हत्यारा बताया

दिल्ली में नमो भारत ट्रेन के दौड़ने की आ गई तारीख, जानें कब से कर सकेंगे सफर; एनसीआर के लोगों को भी फायदा

संजय बाटला

दिल्ली–मेरठ कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन जल्द ही साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के बीच दौड़ेगी। नवंबर से शुरू होने वाले ट्रायल रन के बाद जून 2025 तक दिल्ली से मेरठ तक 82 किमी लंबे संपूर्ण कॉरिडोर पर इसका परिचालन शुरू हो जाएगा। इससे यह दूरी सिर्फ 40 मिनट में पूरी हो सकेगी। इससे यात्रियों को मेरठ से दिल्ली तक आवागमन में आसानी होगी।

नई दिल्ली। दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर आरआरटीएस पर साहिबाबाद से न्यू अशोक नगर के बीच जल्द ही नमो भारत ट्रेन दौड़ेगी। करीब 12 किमी के खंड पर नमो भारत ट्रेन का ट्रायल रन नवंबर से शुरू हो जाएगा। इसके चालू होने से न्यू अशोक नगर और मेरठ साउथ स्टेशनों के बीच की यात्रा 35 से 40 मिनट में हो सकेगी। वहीं अब इसके औपचारिक तरीके से चलने की तारीख भी सामने आ गई है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक शलभ गोयल ने बताया कि जून 2025 में दिल्ली से मेरठ तक 82 किमी. लंबे संपूर्ण कॉरिडोर पर नमो भारत ट्रेन का परिचालन भी शुरू हो जाएगा। इस कारिडोर के साहिबाबाद से मेरठ साउथ के बीच के हिस्से में नमो भारत ट्रेन का परिचालन वर्तमान में हो रहा है। ऐसे में जून 2025 से न केवल मेरठ बल्कि गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली तक के यात्रियों को मेरठ से दिल्ली तक आवागमन करने में आसानी होगी।

न्यू अशोक नगर तक ट्रैक बिछाने का काम पूरा

बता दें, दिल्ली के न्यू अशोक नगर आरआरटीएस स्टेशन की लंबाई लगभग 215 मीटर और चौड़ाई 30 मीटर है। कानकोर्स और प्लेटफॉर्म लेवल पूरे हो चुके हैं और छत का काम प्रगति पर है। न्यू अशोक नगर तक ट्रैक बिछाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। ओएचई और सिग्नलिंग का काम भी प्रगति पर है। आसपास के इलाकों से स्टेशन तक कनेक्टिविटी और पहुंच को बेहतर बनाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) स्टेशन पर दो अतिरिक्त फुट ओवर ब्रिज (एफओबी) का निर्माण भी कर रहा है।

हाईस्पीड मेरठ मेट्रो की घोषणा

बता दें, आज ही मेरठ मेट्रो के शुरू होने की भी घोषणा की गई है। यह नमो भारत ट्रेन के ट्रैक पर ही दौड़ेगी। इसकी अधिकतम 135 और औसत 120 किलोमीटर किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार होगी। इसे देश की सबसे तेज मेट्रो बताया जा रहा है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम डिपो स्टेशन तक 23 किलोमीटर के बीच में मेट्रो के कुल 13 स्टेशन होंगे। इनमें से नौ स्टेशन एलिवेटेड, तीन भूमिगत और एक स्टेशन धरातल पर होगा। इनमें से चार स्टेशन पर नमो भारत ट्रेन का ठहराव भी होगा।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)
TOLWA
website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com
रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण
रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

मेरठ मेट्रो है सबसे खास, स्वदेशी तकनीक से तैयार ट्रेन में यात्रियों को मिलेंगी लग्जरी सुविधाएं; जानें खासियत

मेरठ मेट्रो भारत की सबसे तेज मेट्रो है जिसकी अधिकतम गति 135 किमी प्रति घंटा होगी। यह स्वदेशी तकनीक से निर्मित है और यात्रियों को अधिकतम आराम और सुरक्षा प्रदान करती है। इसमें वातानुकूलित ट्रेनें आरामदायक सीटें सामान रखने की रैक ग्रैब हैंडल यूएसबी डिवाइस चार्जिंग सुविधा आदि हैं। मेरठ मेट्रो के ट्रेन सेट को आधुनिक तरीके से मेक इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार किया गया है।

नई दिल्ली। यूपी के लोगों को जल्द ही मेरठ मेट्रो की सौगात मिलनेवाली है। इसके जून 2025 में शुरू होने की संभावना है। मेरठ मेट्रो की अधिकतम स्पीड 135 किमी प्रति घंटे की होगी। इस मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट मेसर्स एल्सटॉम को दिया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट में 15 सालों तक रोलिंग स्टॉक का रखरखाव भी शामिल है। इसका निर्माण गुजरात के सावली में किया जा रहा है। देश में ऐसा पहली बार है, जब नमो भारत ट्रेनें और मेरठ मेट्रो दोनों ही दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ RRTS के ट्रैक पर चलेंगी।

एनसीआरटीसी के एमडी शलभ गोयल ने बताया कि मेरठ मेट्रो कॉरिडोर की कुल लंबाई 23 किमी है, जिसमें 18 किमी का हिस्सा एलिवेटेड है और 5 किमी का हिस्सा भूमिगत है। मेरठ में कुल 13 स्टेशन हैं, जिनमें से 9 स्टेशन एलिवेटेड और 3 स्टेशन भूमिगत हैं। एक स्टेशन (डिपो स्टेशन) ग्राउंड लेवल पर होगा।

मेरठ मेट्रो में होंगी ये सुविधाएं

मेरठ मेट्रो का डिजाइन बेहद ही आकर्षक और आधुनिक है। इसमें यात्रियों के अधिकतम आराम और सिक्योरिटी को ध्यान में रखा गया है। ट्रेनें वातानुकूलित हैं, जिनमें बैठने की व्यवस्था, सामान रखने की रैक, ग्रैब हैंडल, यूएसबी डिवाइस चार्जिंग सुविधा आदि की हैं।

मेरठ मेट्रो की ट्रेन अत्याधुनिक हल्के वजन और स्टेनलेस स्टील से निर्मित हैं। एक ट्रेन में 173 सीटें होंगी और इसमें 700 से ज्यादा यात्री सफर कर सकेंगे। सभी स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर (पीएसडी) के साथ मेट्रो संचालन को जोड़ा जाएगा।

ऊर्जा खपत में कमी के लिए ट्रेनों के दरवाजों में पुश बटन का प्रयोग किया गया है, जिसकी मदद से सिर्फ वही दरवाजे खुलेंगे, जहां पुश बटन को दबाया जाएगा।

आपातकालीन निकास उपकरण, अग्निशामक यंत्र, अलार्म और टॉक-बैक सिस्टम जैसी सुरक्षा सिस्टम दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति में मेडिकल स्ट्रेचर ले जाने के लिए ट्रेन में जगह की व्यवस्था, व्हील चेयर के लिए भी स्थान होगा।

मेरठ मेट्रो के शुरुआत होने के बाद ये देश में एक अच्छी पहल होगी। इस तरह यह देश में एक कॉरिडोर पर दो तरह की ट्रेनें चलेंगी। मेरठ कॉरिडोर 23 किलोमीटर लंबा होगा। मेरठ मेट्रो के ट्रेन सेट को आधुनिक तरीके से मेक इन इंडिया मुहिम के तहत तैयार किया गया है।

गड्डासुर की आत्मकथा: मानव की लापरवाही और उसके विनाश की कहानी

डॉ. अंकुर शरण

मैं एक साधारण सड़क का हिस्सा था, जिसे कभी लोग आसानी से पार कर लेते थे। लेकिन समय के साथ मेरी किस्मत बदल गई। मैं अब एक गड्ढा (Pot Hole) बन चुका हूँ—गड्डासुर। मेरी कहानी पानी, समय और मानव की लापरवाही से बुनी गई है। आज मैं यहाँ हूँ, अपनी पीड़ा और मानव द्वारा की गई अनदेखी का प्रतीक, जो धीरे-धीरे उनके ही विनाश का कारण बनती जा रही है।

शुरुआत:
सड़क पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया, और बारिश का पानी मेरी सतह पर जमने लगा। यह पानी मेरी मजबूत काया को धीरे-धीरे कमज़ोर करता रहा। शुरुआत में, मैंने अपनी हालत का आभास कराया, लेकिन किसी ने मुझे गंभीरता से नहीं लिया। मेरे शरीर में पहली दरार तब पड़ी, जब भारी ट्रक मेरी पीठ पर से गुजरे, और मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय सहन करने के।

पहली दरार:
जब मेरी सतह पर पहली दरार आई, तो लोग मुझे नजरअंदाज कर आगे बढ़ गए। उन्हें लगता था कि मैं छोटा हूँ और आसानी से पार हो सकता हूँ। यह सोचकर उन्होंने मेरी मरम्मत की कोई चिंता नहीं की। यह लापरवाही ही मेरे विकराल रूप का बीज थी, जो धीरे-धीरे अंकुरित हो रहा था।

बढ़ता आकार:
हर गुजरते दिन के साथ मैं बड़ा होता गया। बारिश के पानी और गाड़ियों के भारी पहियों ने मुझे और गहरा बना दिया। वाहनों की तेज गति और मौसम की बेरहमी ने मेरी सेहत को और बिगाड़ दिया। अब मैं एक छोटा सा गड्ढा नहीं रहा; मैं गड्डासुर बन चुका था—जिससे टकराकर वाहन और यात्री दोनों पीड़ा झेलने लगे।

यात्री की परेशानी:
मेरी वजह से सड़क पर चलने वाले यात्री अब सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे थे। कई बार, बाइक सवार गिरते, कारों के पहिए फटते, और हादसे होने लगते। लोगों को मुझसे डर लगने लगा, लेकिन फिर भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। मेरी स्थिति से अनभिज्ञ प्रशासन मुझे ठीक करने के बजाय और बड़ी समस्याओं को जन्म दे रहा था।

सरकार की उदासीनता:
मैं सड़क की खराब हालत का प्रतीक बन गया था, लेकिन सरकारी अधिकारियों की उदासीनता ने मेरी समस्या को अनदेखा किया। हर गुजरते दिन के साथ मैं और बड़ा हो रहा था, लेकिन कोई भी मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। सरकारी लापरवाही की वजह से मेरी स्थिति दिन-प्रतिदिन विकराल होती जा रही थी।

विरोध और शिकायतें:
स्थानीय लोगों ने कई बार मेरी वजह से हो रही दुर्घटनाओं की शिकायतें कीं। पर उनके विरोध को हमेशा नजरअंदाज कर दिया गया। कोई मेरे अंदर के गहराते संकट को समझ नहीं रहा था। लोग सड़क की मरम्मत की माँग कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज़ें अनसुनी कर दी गईं।

विपदा का समय:
फिर आया बारिश का मौसम, जो मेरे जीवन का सबसे भयावह समय साबित हुआ। बारिश के पानी ने मुझे और भी विशाल बना दिया, जिससे जलजमाव की स्थिति पैदा हो गई। अब लोगों के लिए मुझे पार करना और भी मुश्किल हो गया था। मुझे पार करने में लोग गिरते-पड़ते और अपनी जान जोखिम में डालते थे।

अंतिम चेतावनी:
कुछ सामाजिक कार्यकर्ताओं और मीडिया ने मेरी स्थिति को उजागर किया। रात के समय, मेरी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता था, और हादसे बढ़ने लगे। मैं मानव की लापरवाही का जीवंत उदाहरण बन चुका था। मेरी स्थिति इतनी गंभीर हो चुकी थी कि अब मैं मानव जीवन के लिए एक बड़ी चुनौती बन गया था।

समाधान की प्रतीक्षा:
अब मैं यहाँ हूँ, अपनी मरम्मत की प्रतीक्षा में। मैं जानता हूँ कि जब तक कोई बड़ा हादसा नहीं होगा, तब तक शायद मेरी तरफ ध्यान नहीं दिया जाएगा। लेकिन मैं भी जानता हूँ कि अगर मेरी मरम्मत समय पर नहीं की गई, तो मेरी वजह से होने वाले नुकसान का खामियाजा अंततः मानव को ही भुगतना पड़ेगा। गड्डासुर की यह आत्मकथा एक चेतावनी है—लापरवाही अंततः विनाश का कारण बनती है।

गड्डासुर सिर्फ एक गड्ढा नहीं, बल्कि मानव की लापरवाही और अदूरदर्शिता का प्रतीक है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि छोटी समस्याओं को अनदेखा करना अंततः बड़ी मुसीबतों को जन्म देता है। अब समय है कि हम जागरूक हों, समय रहते समस्याओं का समाधान करें और ऐसी स्थिति को रोके, जहाँ एक साधारण गड्ढा गड्डासुर बन जाए।

दिल्ली के 9 फ्लाईओवर्स होंगे मजबूत, केजरीवाल सरकार कराएगी जीर्णोद्धार; लाखों लोगों को होगा फायदा

दिल्ली सरकार ने यातायात को सुगम बनाने के लिए नौ फ्लाईओवरों के जीर्णोद्धार का फैसला किया है। इनमें अफ्रीका एवेन्यू फ्लाईओवर मोती बाग फ्लाईओवर सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर आईटीओ फ्लाईओवर तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर फ्लाईओवर तिलक नगर मेट्रो फ्लाईओवर मायापुरी व पंजाबी बाग फ्लाईओवर शामिल हैं। इन फ्लाईओवरों के मरम्मत कार्यों के लिए सरकार ने कुछ माह पहले 16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी।

नई दिल्ली। सड़कों के जीर्णोद्धार के साथ-साथ अब दिल्ली सरकार यातायात को सुगम बनाने के लिए नौ फ्लाईओवरों का जीर्णोद्धार कराएगी। इनमें अफ्रीका एवेन्यू फ्लाईओवर, मोती बाग फ्लाईओवर, सावित्री सिनेमा फ्लाईओवर, आईटीओ फ्लाईओवर, तिलक नगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर फ्लाईओवर, तिलक नगर मेट्रो फ्लाईओवर, मायापुरी व पंजाबी बाग फ्लाईओवर शामिल हैं।

इन फ्लाईओवरों के मरम्मत कार्यों के लिए सरकार ने कुछ माह पहले 16 करोड़ रुपये की मंजूरी दी थी, अब इन पर काम शुरू करने की तैयारी की जा रही है। मायापुरी फ्लाईओवरों पर काम शुरू करने के लिए यातायात पुलिस ने मंजूरी दे दी है। जिसके अनुसार 6 सितंबर को शुरू किए गए इस कार्य को 30 दिन के अंदर पूरा किया जाएगा। दिल्ली सरकार के इस कदम से फ्लाईओवरों को मजबूती मिलेगी।

वाहनों के लोड से कंक्रीट की सतह हो रही क्षीण

दिल्ली सरकार के अनुसार पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आने वाले फ्लाईओवरों को बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। फ्लाईओवरों के पुराने होने पर वाहनों के लोड से कंक्रीट की सतह क्षीण हो जाती है और इससे वाहनों की आवाजाही अवरुद्ध होती है।

इसे देखते हुए सरकार द्वारा इसके सुदृढ़ीकरण का काम शुरू किया जा रहा है ताकि आम लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। सुदृढ़ीकरण के बाद रोजाना इनका इस्तेमाल करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा।उन्होंने सरकार ने पीब्ल्यूडी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि फ्लाईओवरों के सुदृढ़ीकरण के कार्यों को समय रहते पूरा किया जाए।

फ्लाईओवरों में होंगे ये काम

सुदृढ़ीकरण व मरम्मत के कार्यों में फ्लाईओवरों के कंक्रीट की मरम्मत,एक्सपेंशन ज्वाइंट्स, बियरिंग आदि की मरम्मत की जाएगी, जिससे फ्लाईओवर का जीवनकाल 20 साल तक बढ़ जाएगा। उल्लेखनीय है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा दिल्ली के फ्लाईओवरों का नियमित रूप से रख-रखाव किया जाता है। हालांकि, यातायात के अत्यधिक दबाव के कारण फ्लाइओवरों में छोटी-मोटी कमियां आ जाती हैं। जिसका पीडब्ल्यूडी के रिपेयर यूनिट द्वारा समय-समय पर मेंटिनेंस किया जाता है।

अगर आपके भी बाल झड़ रहे हैं तो एक्सपर्ट से जानें उसे रोकने का तरीका

हमने डॉक्टर बनानी चौधरी से समझा हेयर फॉल होने का कारण, उसे कैसे रोकें और बालों पर कौनसे ट्रीटमेंट करवाने सुरक्षित है।

हेयर फॉल आज के समय में एक आम परेशानी बन गयी है जिससे सिर्फ पुरुष ही नहीं महिलायें भी जूझ रही हैं। इस समस्या के पीछे लम्बी बीमारी, हार्मोनल परिवर्तन, तनाव, रूसी से लेकर बढती उम्र तक कईं कारण हैं। इसी समस्या पर हमारे शो आस्क दी एक्सपर्ट में हमने बात की डॉक्टर बनानी चौधरी से जो मुंबई के Jaslok Hospital and Research Centre और Sir HN Reliance Foundation Hospital and Research Centre में कंसलटेंट डर्माटोलॉजिस्ट हैं। उनके पास जिर्राट्रिक केर और टॉपिक डर्मिटाइटिस में 15 सालों का एक्सपीरियंस भी है। तो आइये जानते हैं कि इस समस्या पर उन्होंने विस्तार से क्या बताया-

बालों के झड़ने का कारण क्या है और क्या सभी हेयर फॉल एक ही तरह के होते हैं?

अगर हम देखें तो हेयर फॉल प्युबर्टल ऐज से शुरू होकर 60-70 वर्ष की आयु तक रहते हैं जिसे हम नॉर्मल हेयर फॉल कहते हैं। और बहुत बार असामान्य हेयर फॉल भी देखने को मिलता है जो बच्चों में होता है जो स्किन की समस्या होने के कारण होता है। हेयर फॉल के कारण हर अवस्था के हिसाब से अलग होते हैं, युवाओं को सबसे ज्यादा बाल झड़ने के समस्या डैंड्रफ के कारण होती है। मिडिल ऐज में विटामिन, थाइरोइड, आयरन और मिनरल्स की कमी से बाल झड़ते हैं। वृधावस्था में यह आम तौर पर महिलाओं में राजोवृति के कारण और पुरुषों में डायबिटीज के कारण होते हैं। इसके साथ साथ अगर किसी को लम्बे समय तक बुखार हुआ हो जैसे डेंगू, टाइफाइड, या मलेरिया तो उस स्थिति में भी बीमारी ठीक होने के 3 महीने बाद बाल झड़ते हैं।

क्या बालों का झड़ना ठीक किया जा सकता है?

सफ़ेद हुए बालों को काला नहीं किया जा सकता लेकिन हां झड़ते बालों को रोका और फिर से उगाया जा सकता है। बालों को झड़ने से रोकने के लिए हमें सबसे पहले हेयर फॉल का कारण जानना होता है ताकि उसी हिसाब से ट्रीटमेंट किया जा सके। हेयर फॉल के समय में लोग शैम्पू करना छोड़ देते हैं लेकिन हम मेडिकेटिड शैम्पू का इस्तेमाल कर स्कैल्प की देखभाल करने और उसे साफ़ रखने की सलाह देते हैं ताकि आपके बालों की जड़ें मजबूत हो सकें।

क्या पुरुषों और महिलाओं में बालों के झड़ने का कारण अलग-अलग होता है?

पुरुषों में अगर उनके पिता या फिर मामा के बाल कम हैं या ज्यादा झड़ते हैं तो वह पैटर्न आगे आपके साथ भी होगा लेकिन वहीँ महिलाओं में उनकी माँ के बाल अगर कम और हल्के हैं तो उसका असर उन पर आता है। इसके अलावा पुरुषों में डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT Receptors) ज्यादा होते हैं जिससे उनके बालों के झड़ने या गंजापन होने की संभावना महिलाओं के मुकाबले में ज्यादा होती है। इसके अलावा महिलाओं में थाइरोइड, पीसीओडी और मीनोपॉज के कारण भी बाल हल्के और झड़ने लगते हैं।

क्या बाल झड़ना मौसमी है? कौन से मौसम में सबसे ज्यादा बाल झड़ते हैं और क्यों?

मौसम में बदलाव के अलावा आपके स्कैल्प पर कितना पसीना आता है, वह आपके बालों के झड़ने के लिए ज़म्मिेदार होता है। और अगर देखा जाए तो मानसून के मौसम में सबसे ज्यादा पसीना आता है और इस मौसम में नमी के कारण हमारा पसीना सूखता नहीं है इसीलिए मानसून में सबसे ज्यादा हेयर फॉल की समस्या आती है।

क्या शैम्पू कंडीशनर बदलने से हेयर फॉल रोकने में मदद मिल सकती है और कैसे?

अगर पेशेंट को स्कैल्प की कोई परेशानी नहीं है तो शैम्पू बदलने से हेयर फॉल रुक जाता है क्योंकि कभी कभी पेशेंट अपने बालों के मुकाबले ज्यादा ड्राई शैम्पू का इस्तेमाल कर रहा होता है जिससे बाल ज्यादा टूटने और झड़ने लगते हैं। लेकिन स्कैल्प की दिक्कत होने पर शैम्पू में बदलाव से फर्क नहीं पड़ता।

क्या ऑयलिंग से बाल मजबूत होते हैं?

ऑयलिंग बालों के लिए ज़रूरी है और इसे आप बालों पर लगायेंगे तो वह आपके बालों को कंडीशन करेगा लेकिन अगर आप इसे स्कैल्प पर 30 मिनट से ज्यादा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उससे नुक्सान होगा क्योंकि वह तेल बालों की जड़ों के आसपास एक लेयर बना लेगा जिससे बालों की जड़ें कमजोर होंगी। इसलिए कभी भी रातभर के लिए स्कैल्प पर तेल लगाकर ना सोएं।

क्या बालों को गूंथकर रखने से हेयर फॉल कम होता है?

बालों को किसी भी तरह से रखें चाहें खोल कर रखें या बांधकर उससे बालों के झड़ने का कोई लेना देना नहीं है।

हेयर फॉल में बाल कटवाने से भी क्या हेयर फॉल रुकता है?

बालों को कटवाने से भी हेयर फॉल का कुछ फर्क नहीं पड़ता। हेयर फॉल स्कैल्प से जुड़ा है उसका बालों की लम्बाई से कोई सम्बन्ध नहीं है।

गंजेपन की समस्या क्या महिलाओं को भी हो सकती है?

महिलाओं में पुरुषों के मुकाबले डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन (DHT Receptors) कम होते हैं जिससे उनमे ये परेशानी होने की संभावना कम होती है। मर्दों के मुकाबले में महिलाओं में हेयर फाल होने के बावजूद गंजापन होना बहुत कम होता है।

क्या हेयर फॉल सीधे हमारी डाइट से जुड़ा है या फिर इसे रोकने के लिए हमें अपने लाइफस्टाइल में भी बदलाव लाने होंगे?

अगर आपका हेयर फॉल न्यूट्रीशन की कमी से हो रहा है तो आप अपनी डाइट में विटामिन बी12, बी3, आयरन, कैल्शियम शामिल करेंगे तो आपका हेयर फॉल कम हो जाएगा। लेकिन अगर बालों का झड़ना किसी बीमारी जैसे थाइरोइड या पीसीओडी जैसी किसी समस्या के कारण है तो आपको लाइफस्टाइल में भी बदलाव करने होंगे।

सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि सिल्क के सराहने का इस्तेमाल भी हेयर फॉल रोकता है, क्या यह सच है?

नहीं यह बिलकुल एक मिथ्या है ऐसा करने से कभी भी हेयर फॉल रुकता नहीं है।

क्या ज्यादा कंघी करने से भी बाल झड़ते हैं?

अगर आपके बाल ड्राई हैं तो ऐसे में बार बार कंघी करने से वह टूटेंगे लेकिन आपने कंडीशनर या सीरम लगाया है तो कंघी से बाल नहीं टूटेंगे। और कभी भी बालों को सुलझाने के लिए पतली कंघी का इस्तेमाल नहीं करें।

क्या हेयर ट्रीटमेंट से बाल कमजोर होते हैं? और कौन-सा ट्रीटमेंट सुरक्षित है?

किसी भी हेयर ट्रीटमेंट में अगर प्रोडक्ट आपके स्कैल्प पर इस्तेमाल नहीं होता तो वह कभी नुक्सान नहीं करेगा। रेबोंडिंग के अलावा बालों की जड़ों को छोड़कर कोई भी स्मूथनिंग, केराटीन या प्रोटीन ट्रीटमेंट आप करवा सकते हैं।

हेयर कलर बालों के लिए कितना सुरक्षित है?

हेयर कलर भी बालों की जड़ों पर कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। स्कैल्प पर लगने से वह सीधा आपके खून में जाता है जिससे आपको एलर्जी और स्किन की समस्या होने की संभावना रहती है।इसलिए अमोनिया फ्री की साथ साथ पीपीडी फ्री डाई का इस्तेमाल सबसे सुरक्षित है।

क्या हीट प्रोटेक्टर लगाने से हेयर स्टाइलिंग से होने वाले नुक्सान को हम कम कर सकते हैं?

जी हाँ, हीट प्रोटेक्टिंग सीरम आपके बालों पर एक कोटिंग बना देंगा जिससे हीट डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है।

आईफ़ोन 16 के साथ स्मार्टवॉच और एयरपॉड्स भी होंगे लॉन्च, जानें फीचर्स

Apple की आईफोन 16 सीरीज लॉन्च होने में बस एक ही दिन शेष है। कंपनी ने फ्लैगशिप आईफोन लॉन्च करने के लिए इट्स ग्लोटाइम इवेंट की घोषणा की है। जाहिर तौर पर इस इवेंट का आकर्षण नए आईफोन होंगे।

लेकिन कुछ ऐसे भी डिवाइस हैं, जिनका यूजर्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आईफोन के साथ इन्हें भी इवेंट में पेश किया जा सकता है। वहीं इस इवेंट में आईफोन के साथ एपल वॉच, एयरपोड्स भी लॉन्च किए जाएंगे।

iPhone 16

एपल यूजर्स के लिए 9 सितंबर का दिन बेहद खास है। इस दिन एपल के सबसे एडवांस आईफोन ग्लोबली लॉन्च होंगे। आईफोन 16 लाइनअप में चार मॉडल आईफोन 16, प्लस, प्रो और प्रो मैक्स शामिल हैं। सीरीज के प्रो मॉडल्स में बड़ी डिस्प्ले और बैटरी साइज बड़ा होने की उम्मीद है। इस बार आईफोन में AI का भी अच्छा खासा समागम होगा।

Apple Watch

दो साल में पहली बार कंपनी अपने सभी एपल वॉच मॉडल को एक साथ अपडेट करने की तैयारी कर रही है। इसमें एक नया लो-एंड एपल वॉच SE, एक मिड-लेवल Series 10 मॉडल और एक अल्ट्रा 3 होगा। एपल वॉच अल्ट्रा में केवल मामूली बदलाव किए जाएंगे। बाहरी बदलावों के बजाय इंटरनेल अपग्रेड पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। Apple Watch लाइन-अप में सबसे बड़ा अपग्रेड सीरीज 10 मॉडल के साथ होगा। सीरीज 7 के बाद पहली बार फ्लैगशिफ एपल वॉच मॉडल को अपडेट लुक मिलेगा।

एयरपोड्स

एपल एंट्री-लेवल, सेकंड जेनरेशन ईयरबड्स और मिड टियर थर्ड जेनरेशन मॉडल को बदलने के लिए दो नए एयरपॉड्स मॉडल तैयार कर रहा है। दोनों नए सीजन एयरपॉड्स प्रो के समान ही दिखेंगे। इनमें एक नया केस, यूएसबी C चार्जिंग पोर्ट और बेहतर ऑडियो क्वालिटी शामिल होगी।

भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए रावण ने की थी शिव तांडव स्त्रोत की रचना

मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त सच्चे मन से शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशानन ने शिव तांडव स्त्रोत की रचना कब और कैसे की थी।

भगवान शिव के भक्त उन्हें प्रसन्न करने के लिए कई तरह से पूजा करते हैं। सोमवार का दिन भोलेनाथ को समर्पित होता है। वहीं भगवान शिव के भक्त उनकी उपासना और पूजा के लिए युगों-युगों से कई स्त्रोत की रचना की है। भोलेनाथ को समर्पित कई ग्रंथों में कई तरह के स्तोत्र की रचनाओं का उल्लेख मिलता है। लेकिन भगवान शिव को सभी रचनाओं में शिव तांडव स्त्रोत सबसे अधिक प्रसन्न होते हैं। इस स्त्रोत की रचना भगवान शिव के प्रिय भक्त रावण द्वारा रचित है।

मान्यता के अनुसार, जो भी भक्त सच्चे मन से शिव तांडव स्त्रोत का पाठ करता है, भोलेनाथ उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। ऐसे में आज इस आर्टिकल के जरिए हम आपको बताने जा रहे हैं कि दशानन ने शिव तांडव स्त्रोत की रचना कब और कैसे की थी।

ऐसे हुई शिव तांडव स्तोत्र की रचना

बता दें कि ऋषि विश्रवा की दो पत्नियां थीं और उनकी दो संतानें थी। जिनमें से एक का नाम कुबेर और दूसरे पुत्र का नाम दशानन था। लेकिन ऋषि विश्रवा ने कुबेर को लंका का सारा राजपाट ले दिया। लेकिन कुबेर लंका का राजपाट छोड़कर हिमाचल में तपस्या करने चले गए। जिसके बाद कुबेर का राजपाट दशानन को मिल गया। लंका का राजपाट मिलने के बाद रावण अहंकारी हो गया। वह अहंकार में आने के कारण ऋषियों और साधुओं पर अत्याचार करने लगा। जब रावण के अत्याचारों का पता कुबेर को चला, तो उन्होंने दशानन को समझाने का प्रयास किया। ऐसे में नाराज होकर दशानन ने कुबेर की नगरी अलकापुरी पर आक्रमण कर दिया।

इस युद्ध में कुबेर को हराकर दशानन ने पुष्पक विमान छीन लिया और लंका ले जाने लगे। तभी रास्ते में कैलाश पर्वत आ गया और पुष्पक विमान रुक गया और आगे नहीं बढ़ पाता। जिसके बाद रावण कैलाश पर्वत को रास्ते से हटाने की कोशिश करने लगा। जिससे पर्वत हिलने लगता है और सभी शिवगण दशानन के पास आते हैं और रावण को ऐसा करने से रोकते हैं। लेकिन हठी रावण नंदी का अपमान कर कैलाश पर्वत को फिर से हटाने लगते हैं।

वहीं भगवान शिव भी रावण की सारे हरकतों को देख रहे थे। ऐसे में रावण के घमंड को तोड़ने के लिए भोलेनाथ अपने पैर के अंगूठे का हल्का सा स्पर्श पर्वत पर करते हैं। जिससे पर्वत का भार इतना अधिक हो जाता है कि रावण उसने नीचे दबने लगा और बुरी तरह से घायल हो गया। ज्यादा दर्द के कारण वह इतनी तेज-तेज से चिल्लाने लगा। उसकी चीत्कार इतनी भीषण थी कि ऐसा लग रहा था कि प्रलय आ जाएगी।

ऐसे में रावण ने भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिव की स्तुति करने लगा। तब दशानन ने सामवेद में उल्लेखित भगवान शिव के सभी स्तोत्रों का गान करने लगा। रावण की स्तुति से प्रसन्न होकर भगवान शिव कैलाश पर्वत से अपने पैर का अंगूठा हटा देते हैं और रावण को दर्द मुक्त कर देते हैं। दशानन द्वारा भयंकर दर्द में गाया गया स्त्रोत सामवेद का स्त्रोत है। इसी स्त्रोत को शिव स्त्रोत या रावण स्त्रोत के नाम से जाना जाता है।

छोटे पैरों पर बेहद खूबसूरत लगेंगे बिछिया के ये नए डिजाइंस, आप भी करें ट्राई

बिछिया पहनने से आपके पैर खूबसूरत लगें, इसके लिए आपको पैरों के शेप को समझना बेहद जरूरी है। अधिकतर बिछिया में चांदी की डिजाइंस को ज्यादा पसंद किया जाता है। हम आपको छोटे पैरों की बिछिया के नए डिजाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं।

सभी महिलाएं चाहती हैं कि उनके पैर खूबसूरत नजर आएं। इसके लिए अधिकतर विवाहित महिलाएं पैरों में बिछिया पहनना पसंद करती हैं। वहीं मार्केट में आपको कई सारे डिजाइंस देखने को मिल जाएंगे। लेकिन बिछिया पहनने से आपके पैर खूबसूरत लगें, इसके लिए आपको पैरों के शेप को समझना बेहद जरूरी है।

अधिकतर बिछिया में चांदी की डिजाइंस को ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे में हम आपको इस आर्टिकल के जरिए छोटे पैरों के बिछिया के नए डिजाइंस के बारे में बताने जा रहे हैं। साथ ही इनको स्टाइल करने के आसान टिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं।

मॉडर्न डिजाइन बिछिया

अगर आपके पैर छोटे हैं, तो थोड़े स्टाइलिश डिजाइन वाली बिछिया पहन सकती हैं। सिंपल चांदी के डिजाइन वाली बिछिया बेस्ट रहेंगी। यह बिछिया पूरी उंगली को आसानी से कवर कर लेती है। हालांकि इस तरह की बिछिया पहनें तो पैरों के नाखून ज्यादा न बढ़ाएं। आप इस तरह की बिछिया को न सिर्फ ट्रेडिशनल, वेस्टर्न और इंडो वेस्टर्न लुक के साथ स्टाइल कर सकती हैं।

स्टोन डिजाइन बिछिया

फैंसी डिजाइन वाली बिछिया में आप फ्लोरल और स्टोन वाली बिछिया पहन सकती हैं। स्टोन में आपको कई तरह के डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। स्टोन में सबसे ज्यादा मैरून और ग्रीन कलर सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। हर तरह के पैरों में इस तरह की बिछिया अच्छी लगती हैं।

सिंपल चांदी की बिछिया

अगर आप सिंपल डिजाइन वाली बिछिया पहनना पसंद करती हैं, तो आप फूल और अन्य इसी तरह की बिछिया ले सकती हैं। इसमें आपको छोटे या फिर मीडियम डिजाइन देखने को मिल जाएंगे। फैंसी लुक पाने के लिए आप 2-3 उंगलियों में चांदी की बिछिया पहन सकती हैं। यह बिछिया बेस्ट लुक देने में मदद करती है।

ऋषि पंचमी का व्रत करने से मनुष्य नष्ट होते हैं सारे पाप

शुभा दुबे

प्राचीन काल की बात है। सिताश्व नामक राजा ने एक बार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्माजी से पूछा कि हे पितामह! सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत मुझे बताइए और उस व्रत को करने की विधि भी बताइए।

भाद्रपद शुक्ल पंचमी को सप्त ऋषि पूजन-व्रत किया जाता है। ब्रह्म पुराण में उल्लेख है कि इस दिन स्त्रियों को प्रातः स्नान के पश्चात घर में पृथ्वी को शुद्ध करना चाहिए और वहां हल्दी से चौकोर मण्डल बनाना चाहिए। इस मण्डल पर सप्त ऋषियों की स्थापना कर विधि विधान से उनका पूजन करें। इस दिन व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुराण में बताया गया है कि सात वर्षों तक हर बार इसी प्रकार पूजन करने के बाद आठवें वर्ष ऋषियों की सोने की सात मूर्तियां बनवाकर ब्राह्मण को दान करने से पुण्य लाभ होता है।

कथा- प्राचीन काल की बात है। सिताश्व नामक राजा ने एक बार सृष्टि रचयिता भगवान ब्रह्माजी से पूछा कि हे पितामह! सब व्रतों में श्रेष्ठ और तुरंत फलदायक व्रत मुझे बताइए और उस व्रत को करने की विधि भी बताइए। इस पर ब्रह्माजी बोले-हे राजन! आप जिस प्रकार के व्रत के बारे में पूछ रहे हैं वह है ऋषि पंचमी का व्रत। इस व्रत को करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट तो होते ही हैं साथ ही उसको मनवांछित फल भी प्राप्त होता है।

ब्रह्माजी ने राजा सिताश्व को इस बारे में एक कथा सुनाई। विदर्भ देश में एक सदाचारी ब्राह्मण रहता था। उसका नाम उत्तंक था। उसकी सुशीला नाम की पत्नी थी जोकि बड़ी ही पतिव्रता थी। इस दंपत्ति का एक पुत्र और एक पुत्री थी। जब ब्राह्मण की पुत्री बड़ी हुई तो योग्य वर के साथ उसका विवाह कर दिया गया लेकिन विवाह के कुछ समय बाद ही वह विधवा हो गई। इससे ब्राह्मण दंपत्ति को बड़ा शोक हुआ और वह अपनी पुत्री के साथ गंगा तट पर एक कुटिया डाल कर रहने लगे।

एक बार की बात है। ब्राह्मण कन्या जब सो रही थी तो अचानक ही उसके शरीर पर कई सारे कीड़े आ गये। उसने अपनी मां को यह बात बताई तो वह चिंतित हो उठी और ब्राह्मण से कुछ उपाय करने को कहा। साथ ही उन्होंने अपने पति से जानना चाहा कि उनकी कन्या की यह गति होने का क्या कारण है। ब्राह्मण ज्ञानी था उसने अपने ध्यान से यह पता लगा लिया कि उसकी पुत्री की यह गति होने का कारण क्या है। उसने अपनी पत्नी को बताया कि पूर्वजन्म में भी उनकी पुत्री ब्राह्मण कन्या ही थी। उसने एक बार रजस्वला की अवस्था में बर्तनों को छू दिया था। इसके अलावा इसने इस जन्म में भी लोगों को देखने के बावजूद ऋषि पंचमी व्रत नहीं किया। इसलिए इसकी यह गति हुई है और इसके शरीर पर कीड़े आ गये हैं।

ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि यदि यह अब भी शुद्ध मन से और विधिपूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत करे तो इसके सारे कष्ट दूर हो सकते हैं। यह बात सुन उनकी पुत्री ने पूरे विधि विधान के साथ ऋषि पंचमी का व्रत किया तो उसके सारे कष्ट दूर हो गये और अगले जन्म में उसे अच्छा घर और अच्छा पति मिला तथा वह सौभाग्यशाली स्त्री हुई और उसे सभी सुखों का भोग करने का अवसर प्राप्त हुआ।

ट्राई ने फर्जी कॉल रोकने के लिए उठाया नया कदम, अब तक 2.75 लाख फोन नंबर कटे, व्हाट्सऐप और टेलीग्राम से हो रहे हैं फ्रॉड

TRAI ने हाल ही में फर्जी कॉल को रोकने के लिए अब तक 2.75 लाख फोन नंबर कनेक्शन काट दिए हैं। ट्राई ने स्पैम और फ्रॉड कॉल्स को रोकने के लिए लगातर नए कदम उठाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि ऐसी कॉल्स को रोकने के लिए लगातार काम चल रहा है। दरअसल, ट्राई का कहना है कि अभी ऐसे बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं। यह सारे फ्रॉड व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से हो रहे है।

अभी तक ट्राई ने क्यों नहीं लिया फैसला

दरअसल, जितने भी एप्स है वो सभी IT मिनिस्ट्री के अंडर आते हैं। इस पर ट्राई कोई फैसला नहीं ले सकता। क्योंकि ये अधिकार उसके क्षेत्र में नहीं आता। ट्राई के द्वारा भेजे गए पत्र में बताया गया है कि आखिर इन कॉल्स से कैसे बचा बता दें, रेगुलेटर्स की जॉइंट कमेटी ने भी इस बात को रखा है। ऐसे में ट्राई ने अधिकारियों को कॉल्स रोकने के लिए एक्शन लेने के लिए भी कहा है।

आधिकारियों ने बताया है कि ट्राई चाहती है कि इसको लेकर जॉइंट एफर्ट लगाने चाहिए। आपको बता दें कि, ट्राई की तरफ से निर्देश मिलते ही टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने फर्जी कॉल्स को रोकने के लिए DLT प्लेटफॉर्म का प्रयोग करना शुरु कर दिया। ट्राई ने कुछ समय पहले सभी टेलीकॉम ऑपरेटर्स को भी ऐसी कॉल्स और मैसेज को रोकने के लिए कहा था। फिर टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने 1 अक्टूबर तक समय मांगा था।

अचानक धंस गई जनकपुरी की सड़क, PWD अधिकारी के छूटे पसीने; टला बड़ा हादसा

जनकपुरी के जोगिंदर सिंह मार्ग पर अचानक सड़क धंसने से बड़ा गड्ढा हो गया। लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के कारण कोई बैरिकेड नहीं लगाए गए जिससे वाहन चालक जान जोखिम में डालकर गुजर रहे हैं। जल बोर्ड की पाइपलाइन लीक होने से मिट्टी बैठ गई है। इससे पहले भी यह सड़क धंस चुकी है लेकिन विभाग ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की।

पश्चिमी दिल्ली। जनकपुरी स्थित जोगिंदर सिंह मार्ग की सड़क शनिवार सुबह अचानक धंस गई, जिससे लोक निर्माण विभाग की पोल खुल गई। सड़क बीचोबीच धंसने से वहां पर गहरा गड्ढा हो गया। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी लोक निर्माण विभाग को दी। इसके बाद मौके पर विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने 12 से अधिक छोटे ट्रक मिट्टी डालकर गड्ढे को दोपहर तक भरा।

गड्ढे के भराव के दौरान न तो यहां पर विभाग का कोई अधिकारी मौजूद रहा और न ही पुलिस प्रशासन जिसकी वजह से दो पहिया वाहन चालक अपनी मनमानी कर वहां से गुजरते नजर आए, क्योंकि यहां पर बैरिकेड तक की कोई व्यवस्था नहीं थी। ऐसे में कभी भी हादसा हो सकता था। कारों या फिर अन्य बड़े वाहनों के लिए एक तरफ का रास्ता खुला था जिससे लोग आवागमन करते रहे इससे यातायात काफी प्रभावित रहा।

सड़क धंसने से गहरा गड्ढा हो गया

जनकपुरी के जोगिंदर सिंह मार्ग स्थित डिस्ट्रिक्ट सेंटर से लाल सैन मंदिर मार्ग की तरफ आने-जाने वाली सड़क का निर्माण वर्षों पहले कराया गया था। यहां से रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन रहता है। शनिवार सुबह करीबन आठ बजे अचानक सड़क धंस गई, जिससे वहां पर गहरा गड्ढा हो गया। लेकिन इस दौरान वहां पर वाहनों का आवागमन जारी रहा। आसपास के लोगों ने मामले की जानकारी लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) के अधिकारियों को दी।

पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी सुधार में जुटे

पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और उन्होंने सड़क के दोनों ओर बैरिकेड लगाए। उन्होंने गड्ढे को खोलकर सुबह 11 बजे से मिट्टी का भराव कराना शुरू किया, जो कि दोपहर 3 बजे तक चला। इस दौरान ना तो यहां पर पीडब्ल्यूडी का कोई अधिकारी मौजूद दिखा और न ही वाहनों को रोकने के लिए पुलिस मौजूद थी, इस कारण लोग अपनी मनमानी कर जान को जोखिम में डालकर वहां से गुजरते हुए दिखे।

जल बोर्ड की पाइपलाइन लीक होने से हुआ हादसा

सड़क के दोनों कोई बैरिकेडिंग नहीं थे। केवल कागज की पट्टी का सुरक्षा घेरा बना दिया गया जिसे उठाकर दो पहिया वाहन चालक आराम से गुजरते हुए नजर आए। मना करने के बावजूद लोग गड्ढे के पास से निकल रहे थे। ऐसे में यहां पर कभी भी बड़ा हादसा हो सकता था। वहीं इस घटना पर विभाग के अधिकारी का कहना है कि सड़क के नीचे कहीं से जल बोर्ड की पाइप लाइन से पानी लीक हो रहा है जिसकी वजह से अंदर की मिट्टी बैठ गई है। इस कारण सड़क धंस गई है।

पहले भी धंस चुकी है यह सड़क

जोगिंदर सिंह मार्ग पर सड़क धंसने की यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी सड़क एक बार धंस चुकी है। गड्ढे पर मिट्टी डालकर विभाग द्वारा उसे बंद कर खानापूरी कर दी गई। सड़क की मरम्मत तक नहीं कराई गई है। इसके अलावा सड़क धंसने से वाल्मीकि मार्ग पर भी पहले गड्ढा हो गया था।

निर्माण कार्य के नाम पर विभाग द्वारा खानापूरी की जा रही है। इससे पहले भी यह सड़क धंस चुकी है। कई बार शिकायत करने के बाद भी सड़कों की मरम्मत तक नहीं कराई जाती है। जिसकी वजह से जनता को परेशानी का सामना करना पड़ता है। -उर्मिला चावला, पार्षद

मैं सुबह 11 बजे से यहां पर आया हूं। गुजर रहा था तो देखा इतना बड़ा गड्ढा हो गया है। कोई पुलिस और विभाग का अधिकारी नहीं आया है। बैरिकेड नहीं लगे हैं इस वजह से वाहन चालक भी यहां से गुजर रहे हैं। मना करने के बावजूद लोग सुनते नहीं हैं। -अर्जुन सिंह, राहगीर

नफरती बयानों और बुलडोजर के ज़ुल्म की घटनाओं पर कठोर कार्रवाई हो : जमाअत-ए-इस्लामी हिंद की मांग

शम्स आगाज़

नई दिल्ली। जमाअत-ए-इस्लामी हिंद के दिल्ली स्थित केंद्रीय मुख्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को जमाअत के उपाध्यक्ष प्रोफेसर सलीम इंजीनियर और राष्ट्रिय सचिव शफी मदनी ने संबोधित किया। घृणा अपराधों पर बोलते हुए प्रोफेसर सलीम ने कहा कि देश में घृणा अपराध काफी बढ़ गये हैं। कुछ शक्तियां जानबूझकर मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर उन्हें भड़काती हैं ताकि देश में अशांति फैले। यह दुखद है कि असामाजिक तत्व बेखौफ होकर अपराध कर रहे हैं, ऐसा लगता है कि उन्हें पुलिस और राजनीतिक संरक्षकों का समर्थन और संरक्षण प्राप्त है। इसलिए इन्हें न तो कोर्ट से सजा का डर है और न ही गिरफ्तारी का। आरोपियों की संपत्ति को बुलडोजर से नष्ट करने की बात पर उन्होंने कहा कि यह एक गैरकानूनी कृत है जो देश में तेजी से फैल रही है। विध्वंस के निशाने का एक बड़ा प्रतिशत स्पष्ट रूप से धार्मिक अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुसलमानों को बनाया जाता है। राजशक्ति का उपयोग करने के इस अलोकतांत्रिक, निरंकुश और अन्यायपूर्ण तरीके को धूर्ततापूर्वक 'बुलडोजर न्याय' कहा जाता है। इस अवैध विध्वंस के खिलाफ एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गोवाई और केवी विश्वनाथन की पीठ ने सराहनीय टिप्पणी की और अवैध विध्वंस को रोकने की दिशा में प्रगति हुई। जिसमें कहा गया है कि, ₹किसी संपत्ति को सिर्फ

इसलिए नहीं ध्वस्त किया जा सकता क्योंकि वह किसी ऐसे व्यक्ति की है जिस पर कोई अपराध का आरोप है।₹ "हम आशा करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय इस मुद्दे पर अखिल भारतीय स्तर पर दिशानिर्देश निर्धारित करेगा तथा सभी संबंधित प्राधिकारियों द्वारा उन दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा।" नफरती भाषणों के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में एक धार्मिक नेता द्वारा पैगंबर मुहम्मद (स.अ.व.) और इस्लाम के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा करती है और कानूनी कार्रवाई तथा उनकी तत्काल गिरफ्तारी की मांग करते हैं। घृणास्पद भाषणों के विरुद्ध स्वतः कार्रवाई करने के भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश का सख्ती से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए, तथा ऐसा करने में पुलिस द्वारा की गई किसी भी आनाकानी को न्यायालय की अवमानना माना जाना चाहिए।

जमाअत के राष्ट्रिय सचिव शफी मदनी ने असम के हालात पर बात करते हुए कहा असम के बारपेटा जिले के 28 बंगाली मुसलमानों को 'विदेशी ट्रिब्यूनल' द्वारा विदेशी घोषित कर ट्रांजिट कैंपों में भेजे जाने की कड़ी निंदा करती है। उन्हें विदेशी घोषित करने और ट्रांजिट कैंपों में भेजने के लिए कानून की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया। यह उनके मौलिक अधिकारों का घोर उल्लंघन है। उन्हें अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जानकारी भी नहीं थी। संसाधनों की कमी के कारण उन्होंने उच्च न्यायालय में मामले को चुनौती दे सके। ट्रिब्यूनल का यह फैसला मुस्लिम समुदाय, खासकर 'मियां बंगाली मुसलमानों' को अनुचित तरीके से निशाना बनाए जाने का प्रमाण है। सिर्फ मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया है जबकि असम एनआरसी प्रक्रिया से पता चला कि विदेशियों के रूप में पहचाने गए लोगों में से दो तिहाई हिंदू और एक तिहाई मुसलमान थे। लेकिन इन कानूनों को लागू करते समय, विशेष रूप से प्रवर्तन में, ट्रिब्यूनल ने मुसलमानों को असंगत रूप से निशाना बनाया गया है और उन्हें अन्यायपूर्ण तरीके से हिरासत में रखा गया है। उन्होंने कहा कि जमाअत गलत तरीके से एनआरसी कार्यान्वयन द्वारा प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है और पीड़ितों को कानूनी और नैतिक रूप से समर्थन देगी। जमाअत मांग करती है कि सरकार इन कदमों की तुरंत समीक्षा करे और यह सुनिश्चित करे कि किसी भी मूल नागरिक को विदेशी न करार दिया जाए और उसे हिरासत में लेकर परेशान न किया जाए। प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा और अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, चाहे वह किसी भी जाति, पंथ या धर्म का हो।

भाजपा संविधान को कमजोर करने की कोशिश कर रही है- देवेन्द्र यादव

सुषमा रानी

नई दिल्ली, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने कहा कि जिस तरह भाजपा लम्बे समय से संविधान पर प्रहार करके उसे कमजोर करने की कोशिश कर रही है उसी तरह आम आदमी पार्टी भी संविधान के अंतर्गत दलितों के अधिकारों को छीनने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी की मेयर शैली ऑबराय ने तीसरे टर्म में दलित पार्षद का मेयर बनने के अधिकार को छीनकर जबरन 5 महीने से मेयर के पद पर अधिपत्य जमाए बैठी हैं। जबकि एमसीडी अधिनियम (धारा-35) में प्रावधान अनुसार 31 मार्च, 2024 को मेयर का कार्यकाल समाप्त होने के बाद दलित मेयर बनना था।

देवेन्द्र यादव ने कहा जब कांगेस दिल्ली की सत्ता में थी तब दलितों के उत्थान और कल्याण के लिए कई योजनाएं लागू की, जिनमें दलित पिछड़े वर्ग के बच्चों को शिक्षा, उच्च शिक्षा, वजीफा आदि सुविधा देकर सशक्त बनाया जिसे केजरीवाल सरकार ने पूरी तरह से खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि दलितों के लिए कॉलेज/विश्विद्यालय के छात्रों के लिए मेरिट छात्रवृति के तहत 2013-14 में शीला सरकार ने 7163 छात्रों को लगभग 5.80 करोड़ रुपये दिए जो 2022-23 में घटकर केवल 1563 छात्रों को 1.61 करोड़ रह गए जो दिसम्बर 2023 तक 815 छात्रों को 74 लाख मिले थे। उन्होंने कहा कि पब्लिक स्कूल में एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक छात्रों के लिए ट्यूशन फीस की प्रतिपूर्ति 2022-23 में 28315 की तुलना में 2023-24 में घटकर 6860 हो गई है, जो पिछले वर्ष के अनुपात में एक चौथाई रह गई है। उन्होंने कहा कि शडूल कास्ट सब प्लान के अंतर्गत 2023-24 में 246 करोड़ का बजट आंवटित हुआ जिसमें दिसम्बर, 2023 तक सिर्फ 37.18 करोड़ खर्च हुआ जो आवंटित राशि का सिर्फ 15.11 प्रतिशत था। इसी तरह एससी/एसटी/ओबीसी छात्रों के लिए मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रतिभा योजना की राशि आधी रह गई। 2023-24 दिसम्बर, 23 तक 3599 छात्रों के लिए 1.56 करोड़ रह गई जबकि 2023 में 15491 छात्रों के लिए 11.23 करोड़ थी। विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वित्तिय सहायता के रुप में दलित छात्रां को मिलने वाली ट्यूटशन फीस की प्रतिपूर्ति में भी केजरीवाल सरकार ने भारी कटौती की है।

देवेन्द्र यादव ने कहा कि हमारे नेता राहुल गांधी की भाजपा की तानाशाह सरकार के खिलाफ और संविधान को बचाने की लड़ाई से प्रेरित होकर दूसरे दलों के नेता लगातार कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे है। इसी कड़ी में कल आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री राजेन्द्र पाल गौतम कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए और कुछ समय पहले एक और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री भी आम आदमी पार्टी छोड़ चुके है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी में दलितों का विश्वास खत्म हो गया है क्योंकि पिछले 11 वर्षों में दलित समाज का हमेशा शोषण किया है, जबकि आप पार्टी ने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सिर्फ दलितों को वोट बैंक के रुप में इस्तेमाल किया है। उनसे किया गया एक भी वायदा आज तक नही निभाया है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस एकमात्र ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो संविधान को बचाने की बात करती है और दलितों, पिछड़ों, वंचितों को बचाने और उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ रही है। श्री देवेन्द्र यादव ने कहा कि आप पार्टी के शासन में शोषित, वंचित वर्गों के कल्याण की योजनाओं के बजट में लगातार कटौती की जा रही है और दलित समाज के कल्याण और दलित छात्रों के विकास और सुविधाओं के लिए जो बड़े-बड़े वायदे किए थे वो सिर्फ घोषणा बनकर रह गए।

एलजी साहब अपने कार्यक्षेत्र में विफल होने पर वो "आप" को जिम्मेदार ठहराते हैं-

सुषमा रानी

नई दिल्ली, मयूर विहार फेस-3 के एक नाले में डूबने से हुई मां-बेटे की मौत मामले में भाजपा के एलजी के झूठ की पोल खुलने पर आम आदमी पार्टी ने उनसे माफी मांगने और अपने पद से इस्तीफा देने की मांग की है। "आप" की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने कहा कि 31 अगस्त को जिस नाले में यह घटना हुई थी, भाजपा उसे पीडब्ल्यूडी का बता रही थी। लेकिन अब हाईकोर्ट में साबित हो गया है कि यह नाला डीडीए का है। इसके बाद भी एलजी साहब ने दोषी अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने डीडीए को फटकार भी लगाया और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का आदेश दिया है। वहीं, घटना के बाद जब "आप" ने विरोध प्रदर्शन और प्रेसवार्ता कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का दबाव बनाया तो एलजी साहब ने चिट्ठी लिखकर नाला डीडीए का होने से इन्कार कर दिया था। उन्होंने कहा कि एलजी साहब अक्षम, निकम्मे और बेहद झूठी पार्टी के सदस्य हैं। जब वो अपने कार्यक्षेत्र में विफल होते हैं तो "आप" को जिम्मेदार ठहराते हैं।

आम आदमी पार्टी की मुख्य प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि 31 जुलाई 2024 को मयूर विहार फेस-3 में डीडीए के 15 फीट गहरे नाले में गिरकर एक ढाई साल के बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई थी। घटना की सूचना मिलते ही हमारे स्थानीय विधायक कुलदीप कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने जेसीबी बुलवाकर मृत मां-बेटे को नाले से बाहर निकलवाया और पीड़ित परिवार की पूरी मदद की। कुलदीप कुमार ने यह नहीं सोचा कि नाला किसके अधीन है। 1 अगस्त को भी जब डीडीए के अध्यक्ष एलजी साहब ने पीड़ित परिवार के मुआवजे की घोषणा नहीं की और न ही पीड़ित परिवार से मुलाकात की। इसके बाद सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता कर एलजी साहब से पूछा कि जब वे संकट के समय दिल्लीवालों के साथ खड़े नहीं रह सकते, तो उनका इस संवैधानिक पद पर बैठे रहने का क्या हक़ बनता है, जबकि उनके अधीन डीडीए की लापरवाही से ये घटना हुई है। उन्होने कहा कि इसके बाद भाजपा ने अपने एक ओछे प्रवक्ता को घटनास्थल पर भेजकर यह बताने की कोशिश की कि नाला दिल्ली सरकार के पीडब्ल्यूडी का है।

उम्मीदवार और टिकट

हरियाणा के उम्मीदवार,
कह रहे हैं शान से।
टिकट मिले ना मिले,
लड़ेंगे की जान से।
आलाकमान जो चाहे,
अब वह नहीं होगा।
हम जो भी कहेंगे,
अब वही सही होगा।
देख रहे हैं राह,
मिलेगा हमको टिकट?
नहीं मिला हमको तो,
परिस्थिति होगी विकट।
विरोधी पार्टी से मिल,
हम सुलझा लेंगे संकट।
जब जीतेंगे चुनाव,
तब कहलाएंगे विधायक।
हो जाएंगे तब हम,
सब मंत्री बनने लायक।

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)

दिल्लीवासी ध्यान दें! वोटर लिस्ट में नहीं है नाम तो हो जाएं एक्टिव; अगले महीने शुरू हो रहा विशेष अभियान

राजधानी दिल्ली में निर्वाचन आयोग 29 अक्टूबर से 28 नवंबर के बीच विशेष अभियान चलाया जाएगा जिसमें मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए अगले एक जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नवयुवक आवेदन दे सकते हैं। छह जनवरी को मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय अंतिम मतदाता सूची जारी करेगा। अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए यह मतदाता सूची अहम होगी।

नई दिल्ली। राजधानी में इन दिनों बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और पता का निरीक्षण कर रहे हैं, ताकि मतदाता सूची में सुधार किया जा सके। इसी क्रम में अगले माह 29 अक्टूबर से विशेष सारांश मतदाता सूची संशोधन अभियान शुरू होगा। तब अगले एक जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले नवयुवक भी मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन दे सकते हैं, जो अगले अगले दिल्ली विधानसभा चुनाव में पहली बार मतदान कर सकेंगे। इस विशेष सारांश मतदाता सूची संशोधन अभियान के लिए 29 अक्टूबर को दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय (सीईओ) द्वारा ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसके बाद 29 अक्टूबर से 28 नवंबर तक मतदाता और राजनीतिक दल मतदाता सूची में किसी तरह गलती या गड़बड़ी होने पर उसमें सुधार के लिए शिकायत कर सकते हैं।

ऐप के जरिए भर सकते फॉर्म छह

इस दौरान ही अगले एक जनवरी तक 18 वर्ष की उम्र पूरी करने वाले लोग मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फार्म छह ऑनलाइन भर कर दे सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में फॉर्म भरकर जमा भी कराया जा सकता है। 24 दिसंबर तक मतदाता सूची में गलतियों की शिकायतों का निबटारा किया जाएगा। इसके बाद अगले छह जनवरी को अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी।

घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम-पते का हो रहा मिलान

इसके मद्देनजर बीएलओ अभी घर-घर जाकर मतदाताओं के नाम और पते का मिलान कर रहे हैं। इसलिए 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सीईओ कार्यालय की वेबसाइट पर मौजूद वर्तमान मतदाता सूची में अपने नाम व पते की जांच कर सकते है। यदि नाम में कोई गलती हो या पता बदलवाना हो तो इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। इसके अलावा 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके नवयुवक भी मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए अभी आवेदन दे सकते हैं।

रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगाना अनुचित, मोदी सरकार वापस ले प्रस्ताव : डॉ. संदीप पाठक

सुषमा रानी

नई दिल्ली। मोदी सरकार के टैक्स टेररिज्म का दायरा बढ़ते-बढ़ते अब रिसर्च कर रहे छात्रों की स्कॉलरशिप तक पहुंच गया है। मोदी सरकार ने 2017 से रिसर्च इंस्टीट्यूट को मिल रहे ग्रांट्स पर टैक्स लगाने का प्रस्ताव दिया है। "आप" के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) डॉ. संदीप पाठक ने प्रस्ताव की कड़ी निंदा करते हुए मोदी सरकार से इसे वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह दुनिया के इतिहास में पहली बार है, जब कोई सरकार रिसर्च ग्रांट पर टैक्स लगा रही है। सरकार ने सभी रिसर्च इंस्टीट्यूट को जीएसटी जमा करने के लिए शो कॉज नोटिस दिया है। सरकार तर्क दे रही है कि रिसर्च एक सर्विस है। इसलिए इसके लिए मिले ग्रांट्स पर जीएसटी लगनी चाहिए, जोकि बहुत ही हास्यास्पद है। क्योंकि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर समेत किसी भी विकसित व विकासशील देश में रिसर्च ग्रांट पर टैक्स नहीं लगता है। समस्त मानव जाति और देश के विकास के लिए होने वाले रिसर्च पर जीएसटी लगाना टैक्स टेररिज्म है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव (संगठन) एवं सांसद डॉ. संदीप पाठक ने शनिवार को पार्टी मुख्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि कुछ दिन पहले मोदी सरकार ने रिसर्च ग्रांट्स पर टैक्स लगाया है जो उसकी नियत और टैक्स टेररिज्म पॉलिसी का बड़ा भयानक अध्याय है। केंद्र सरकार ने 2017 से देश की रिसर्च संस्थाओं को दिए ग्रांट्स पर जीएसटी लगाने का प्रस्ताव दिया है और सभी संस्थाओं को 2017 से अब तक मिले रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी जमा करने के लिए शो कॉज नोटिस दिया है। सरकार ने इन संस्थाओं से करीब 220 करोड़ रुपए जीएसटी के रूप में मांगे हैं। इसमें आईआईटी दिल्ली जैसे देश के प्रतिष्ठित संस्थान भी शामिल हैं।

उन्होंने कहा कि भारत ही नहीं, बल्कि दुनिया के इतिहास में पहली बार कोई सरकार रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी लगा रही है। मोदी सरकार का तर्क है कि रिसर्च एक सर्विस है और यह सर्विस उपलब्ध करा रही है। इसलिए ग्रांट्स पर जीएसटी लगनी चाहिए। सरकार का यह तर्क बहुत हास्यास्पद है, क्योंकि कोई भी रिसर्च समस्त मानवजाति के लिए होता है और यह भविष्य में सभी लोगों की सेवा के लिए जरूरी होता है। रिसर्च और आरएनडी देश को आगे बढ़ाता है। इस पर देश का विकास आधारित है और सरकार उसी पर टैक्स लगा रही है। यह पूरी तरह से टैक्स टेररिज्म है।

डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि आम आदमी पार्टी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव की घोर निंदा करती है। आगामी दिनों में जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। केंद्र सरकार को बिना शर्त के इस फैसले को वापस लेना चाहिए। अगर इसे वापस नहीं लिया जाता है, तो आम आदमी पार्टी हर मंच पर इसके विरोध में आवाज उठाएगी, ताकि सरकार इस पॉलिसी को वापस ले।

डॉ. संदीप पाठक ने कहा कि रिसर्च के लिए मिलने वाली फंडिंग तो तीन जगह खर्च की जाती है। इससे रिसर्च के बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती है, संस्थानों में रिसर्च के लिए चीजें खरीदी जाती हैं और रिसर्च से संबंधित जरूरी उपकरण खरीदे जाते हैं। ये सभी चीजें खरीदते वक्त भी संस्थाएं जीएसटी देती हैं। मोदी जी अपने दोस्त अडाणी-अंबानी पर टैक्स लगाने के बजाय रिसर्च के बच्चों को मिलने वाले 20-25 हजार रुपए की स्कॉलरशिप पर टैक्स लगाने जा रहे हैं, जबकि उन्हें रिसर्च पर लगने वाले सारे टैक्स को पूरी तरह हटा देना चाहिए। लेकिन टैक्स हटाने के बजाय दोगुना टैक्स लगा रहे हैं।

उन्होने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी, साउथ कोरिया, सिंगापुर, कनाडा जैसे किसी भी विकसित या विकासशील देश में रिसर्च पर टैक्स नहीं लगता है। दुनिया के इतिहास में केवल मोदी सरकार आरएनडी पर टैक्स लगाने का परचम लहरा रही है। केंद्र की भाजपा सरकार से हमारा निवेदन है कि वह देश को बर्बाद न करें और इस टैक्स को तुरंत वापस ले। अमेरिका अपने देश में बच्चों को रिसर्च के लिए हर साल 57 बिलियन डॉलर देता है और चीन 87 बिलियन डॉलर देता है, जबकि भारत मात्र 2.5 बिलियन डॉलर ही देता है। यह देश के साथ बहुत बड़ा मजाक है। एक तरफ सरकार रिसर्च में पैसा नहीं दे रही है और जो पैसे दे रही है, उस पर भी टैक्स लगा रही है।

उन्होंने कहा कि हमारे रिसर्च के छात्र आज अपने अनुसंधान का दायरा बढ़ा रहे हैं और नई-नई चीजों पर रिसर्च कर रहे हैं और भविष्य में और अच्छा करने की इच्छा रखते हैं। लेकिन ये देखने वाली बात है कि सरकार उनके लिए क्या कर रही है। एक छोटे से टेस्ट करने के लिए रिसर्चर्स को महीनों इंतजार करना पड़ता है। बड़े से बड़े संस्थानों में भी एक रिसर्च पूरा करने में कई बार 6-7 महीने या उससे भी ज्यादा समय लग जाता है। क्या मोदी जी ने उन रिसर्चर्स के साथ बात करके उनकी समस्याओं के बारे में जानने की कोशिश की है? क्या उन्होंने सोचा है कि पीएचडी करने वाले छात्रों के रोजगार की क्या स्थिति है? उनको रोजगार मिल रहा है या नहीं? मोदी सरकार ने आरएनडी को ध्यान में रखकर कभी कुछ नहीं किया। इन्हें इसकी कोई जानकारी नहीं है। इन्हें केवल डंडा चलाने से मतलब है। मोदी सरकार ने मिडिल क्लास के लोगों पर टैक्स लाद-लादकर उनका जीवन तबाह कर दिया है। इससे निकलकर अब सरकार धीरे-धीरे रिसर्च और शिक्षा पर टैक्स लादने की ओर बढ़ रही है। भाजपा और मोदी जी को समझना होगा कि इससे देश आगे नहीं बढ़ेगा।

185 करोड़ रुपये के साथ जीडीए ने इंदिरापुरम आवासीय योजना नगर निगम को सौंपा, पढ़ें क्यों हुआ ऐसा

परिवहन विशेष न्यूज

GDA News यूपी के मेरठ में आयोजित हुई जीडीए की 166वीं बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम आवासीय योजना को नगर निगम के हवाले कर दिया गया। अब जीडीए को 185 करोड़ रुपये नगर निगम को देना है। इसको लेकर जीडीए वीसी और नगरायुक्त के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। खबर के माध्यम से पढ़ें पैसों का भुगतान कैसे होगा और यह क्यों किया गया।

गाजियाबाद। मेरठ में जीडीए की 166वीं बोर्ड बैठक में इंदिरापुरम आवासीय योजना (Indirapuram Housing Scheme) को नगर निगम के हैंडओवर कर दिया गया। वीसी अतुल वत्स और नगर आयुक्त के बीच मंडलायुक्ज सेल्वा कुमार जे. की उपस्थिति में इंदिरापुरम योजना को हस्तांतरण करने पर सैद्धांतिक सहमति बनी।

जीडीए अब नगर निगम को 185 करोड़ रुपये देगा, जिसकी पहली किस्त के रूप में जीडीए 70 करोड़ रुपये देगा। इसके बाद बहु प्रतिक्षित इंदिरापुरम आवासीय योजना के हैंडओवर की प्रक्रिया शुरू होगी।

इंदिरापुरम आवासीय योजना 1200 एकड़ भूमि पर विकसित की गई है, जिसमें करीब साढ़े चार लाख की आबादी निवास करती है। वर्ष 2009 में योजना को पूर्ण विकसित घोषित कर 2011 में जीडीए ने इस योजना को नगर निगम को हैंडओवर करने का प्रयास किया था।

इस योजना के हैंडओवर के लिए नगर निगम में शामिल होने से क्षेत्र के विकास को रफ्तार मिलेगी। इंदिरापुरम योजना में पेयजल को लेकर भी लोग समस्याओं से रूबरू हैं। पेजयल के लिए जीडीए 29 करोड़ रुपये नगर निगम को देगा।

इससे नलकूप, पाइपलाइन, ओएचटी की मरम्मत आदि का कार्य होगा। सोलिड वेस्ट मेनेजमेंट के लिए कूड़ा ट्रांसफर स्टेशन के लिए चार हजार वर्ग मीटर और एमआरएफ के लिए साढ़े चार हजार वर्ग मीटर जमीन जीडीए छह माह में 15 करोड़ रुपये भी देगा। इंदिरापुरम में मूलभूत समस्याओं से लोगों को निजात मिलेगी।

नाले और नालियों के लिए होगा भुगतान

आवासी योजना इंदिरापुरम में करीब 135 किमी नालें निर्मित है। इसके लिए जीडीए 50.31 करोड़ रुपये निगम को देगा। इससे नालों की मरम्मत व नवीनीकरण कराया जाएगा। इससे जलभराव की समस्या भी दूर होगी। स्ट्रीट लाइट के लिए 13.69 करोड़ रुपये का जीडीए भुगतान निगम को करेगा।

नगर निगम करेगा पार्कों की देखभाल

जीडीए उद्यान कार्यों के लिए 11 करोड़ रुपये नगर निगम को देगा। नीति खंड दो में दो कमरे और उद्यान नर्सरी में पूर्व की भांति अधिकतम छह माह तक प्राधिकरण द्वारा उपयोग किया जाएगा। नगर निगम क्षेत्र के पार्क, हरित पट्टियां, गोल चक्कर का सुंदरीकरण और साफ सफाई कराएगा। जीडीए द्वारा संचालित सामुदायिक केंद्र व उससे होने वाली आय पर निगम करेगा। नीति खंड दो का साइट आफिस नगर निगम को जोनल कार्यालय के रूप में मिलेगा।

तीन माह जीडीए करेगा सहयोग

इंदिरापुरम के हैंडओवर पर नगर निगम को शासन से अतिरिक्त स्टाफ मिलेगा, लेकिन तीन माह जीडीए का वर्तमान स्टाफ निगम का सहयोग करेगा। एक महीने में जीडीए इंदिरापुरम की ओर से वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी उपबल्ध कराई जाएगी।

हस्तांतरण तिथि से भवन-कर, जल-कर व सीवर कर लेने का अधिकार नगर निगम को होगा। नर्सरी भी नगर निगम को हैंडओवर होगी। हैंडओवर के बाद नगर निगम कर वसूलेगा।

ऐसे होगी भुगतान प्रक्रिया

नगर निगम हैंडओवर की धनराशि संयुक्त खाता खोलकर दी जाएगी। हैंडओवर पर जीडीए 70 करोड़ रुपये एकमुश्त देगा। बाकी धनराशि तीन किस्तों में दी जाएगी। इसमें 31 दिसंबर 2024 तक 40 करोड़, 31 मार्च 2025 तक 40 करोड़ और एक जुलाई 2025 तक 35 करोड़ रुपये का भुगतान जीडीए नगर निगम को देगा।

हैंडओवर के लिए पांच बार बनी समिति

इंदिरापुरम आवासीय योजना को हैंडओवर करने के लिए प्राधिकरण और नगर निगम के बीच पांच बार समिति गठित हो चुकी। हर बार समिति की ओर से संयुक्त रूप से इंजीनियरिंग और उद्यान अनुभाग की ओर से सर्वे किया गया। अधूरे कार्य और फंड को लेकर दोनों विभागों में सहमति न बन पाने पर यह हैंडओवर नहीं हो सका था। इस बार यह छठी बार के प्रयास में नगर निगम को हैंडओवर हो सकी।

गाजियाबाद के लोगों के लिए गुड न्यूज, गृहकर जमा करने पर मिल रही 10 प्रतिशत की छूट; 35 हजार फ्लैट मालिक रडार पर

गाजियाबाद नगर निगम ने संपत्ति कर जमा न करने वाले करीब 35 हजार फ्लैट मालिकों को नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। सितंबर महीने में गृह कर जमा करने पर 10% की छूट मिलेगी। इसके बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी। नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर टैक्स वसूली के लिए हर हफ्ते समीक्षा की जा रही है।

गाजियाबाद। गृहकर जमा न करने वाले करीब 35 हजार फ्लैट मालिक नगर निगम के रडार पर हैं। नगर निगम की टीम ने जोनवार ऐसे बकायेदारों को चिह्नित कर लिया है। अब इन सभी बकायेदारों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए गए हैं।

निगम अधिकारियों का प्रयास सभी बकायेदारों से 100 प्रतिशत कर वसूली का है। सितंबर माह में गृहकर जमा कर बकायेदार 10 प्रतिशत छूट का लाभ ले सकते हैं। इसके बाद सभी बकायेदारों खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

गृहकर वसूली के लिए नगर आयुक्त कर रहे प्रयास

नगर निगम के मुख्य कर निर्धारण अधिकारी डॉक्टर संजीव सिन्हा ने बताया कि बकायेदारों के गृहकर की वसूली के लिए नगर आयुक्त विक्रमादित्य सिंह मलिक के निर्देश पर चौतरफा प्रयास किए जा रहे हैं। इस कड़ी में लोगों की सहूलियत के लिए गृहकर जमा करने के लिए सोसायटियों में शिविर भी लगवाए जा रहे हैं। इसके अलावा नगर निगम के अंतर्गत आने वाले सिटी, कविनगर, मोहननगर, वसुंधरा, विजयनगर पांचों जोन में हर हफ्ते टैक्स की वसूली की समीक्षा की जा रही है।

जुर्माने से बचने के लिए गृहकर जमा करने के निर्देश

नगर आयुक्त के निर्देश पर मुख्य कर निर्धारण अधिकारी खुद इसकी समीक्षा कर रहे हैं। साथ ही सोसायटियों में कैंप लगाकर नगर निगम की टीम लोगों को गृहकर जमा करने के लिए जागरूक कर रही है। लोगों से अपील की जा रही है कि शहर को स्वच्छ बनाने में सहयोग दें और दंड ब्याज से बचने के लिए समय से गृहकर जमा करें।

मालूम हो कि शहर की विकास रफ्तार को गति देने के लिए नगर निगम अधिकारियों का विशेष फोकस टैक्स की वसूली कर निगम की आय बढ़ाने पर है। यही कारण है कि एक अप्रैल 2023 से 31 अगस्त 2023 तक जहां 84 करोड़ 61 लाख रुपये टैक्स की वसूली हुई थी। वह इस साल इस समयावधि में बढ़कर 148 करोड़ 15 लाख की वसूली हुई है।

इस माह CM योगी आ सकते हैं गाजियाबाद, 15 हजार से ज्यादा लोगों को मिलेगा रोजगार; प्रशासन ने की तैयारी शुरू

गाजियाबाद शहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सितंबर के माह में इसी सप्ताह में गाजियाबाद आने वाले थे लेकिन व्यस्त कार्यक्रम के कारण नहीं आ पाए। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि वह 14 सितंबर को दौरा कर सकते हैं। इस दौरान कई तरह के प्रोग्राम भी होंगे।

गाजियाबाद। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव (Ghaziabad By-Election 2024) को लेकर मतदाताओं को साधने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 सितंबर को गाजियाबाद आ सकते हैं। इसको लेकर तैयारी तेज कर दी गई है, पहले संभावना थी कि मुख्यमंत्री सितंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। कार्यक्रमों की व्यस्तता के कारण अब गाजियाबाद में उनका कार्यक्रम 14 सितंबर को होने की उम्मीद है।

रामलीला ग्राउंड में बड़े स्तर पर होगा कार्यक्रम

मुख्यमंत्री (CM Yogi Adityanath) के आगमन पर घंटाघर स्थित रामलीला ग्राउंड में बड़े स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस दौरान रोजगार मेले का आयोजन 15 हजार से अधिक लोगों को सौ से अधिक निजी कंपनियों में विभिन्न पदों पर नौकरी दिलाने की तैयारी जिला प्रशासन द्वारा की गई है।

पात्र विद्यार्थियों को स्मार्टफोन और टैबलेट दिए जाएंगे। इसके अलावा स्वरोजगार के लिए चयनित लाभार्थियों को मुख्यमंत्री ऋण वितरण भी करेंगे। गाजियाबाद शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर ही कार्यक्रम स्थल के रूप में घंटाघर स्थित रामलीला मैदान का चयन किया गया है।

मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह

यहां पर अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री द्वारा उपचुनाव को लेकर मतदाताओं को साधने का प्रयास किया जाएगा। लगातार दूसरे महीने गाजियाबाद में मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर भाजपा नेताओं में उत्साह है। भाजपाइयों का मानना है कि उपचुनाव से पहले शहर में मुख्यमंत्री के जितने ज्यादा कार्यक्रम होंगे, पार्टी को उतनी अधिक मजबूती मिलेगी।

गुरुग्राम की दो सीटों पर कांग्रेस कल घोषित कर सकती है प्रत्याशी, बाकी सीटों पर फंसा पेंच

हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने शुक्रवार को पहली लिस्ट जारी की थी लेकिन इसमें गुरुग्राम जिले की एक भी सीट शामिल नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिले की दो विधानसभा सीटों बादशाहपुर और पटौदी के लिए रविवार को प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है।गुड़गांव और सोहना सीट को फिलहाल होल्ड रखा गया है।

गुरुग्राम। भाजपा ने गुड़गांव, बादशाहपुर और सोहना सीट पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी शुक्रवार को पहली लिस्ट जारी की थी, लेकिन इसमें गुरुग्राम जिले की एक भी सीट शामिल नहीं थी। पार्टी सूत्रों का कहना है कि जिले की दो विधानसभा सीटों बादशाहपुर और पटौदी के लिए रविवार को प्रत्याशी की घोषणा हो सकती है।

गुड़गांव और सोहना सीट को फिलहाल होल्ड रखा गया है। आम आदमी पार्टी (AAP) से गठबंधन की दशा में इन सीटों पर फेरबदल संभव है।

इन सीटों पर नाम किए फाइनल

पार्टी सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति ने सोहना, तिगांव, भिवानी और गुड़गांव विधानसभा सीट को छोड़कर बाकी अन्य सीटों पर सभी प्रत्याशी फाइनल कर लिए हैं। रविवार रात कांग्रेस प्रत्याशियों की एक और लिस्ट जारी कर सकती है। इसमें बादशाहपुर और पटौदी सीट से भी घोषणा संभव है।

कौन हैं प्रत्याशी की दौड़ में शामिल

बादशाहपुर सीट से राव धर्मपाल के बेटे व वरिष्ठ कांग्रेस नेता विरेंद्र यादव और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव वर्धन यादव का नाम टिकट की दौड़ में है। इन्हीं में से किसी को पार्टी मैदान में उतार सकती है। वहीं पटौदी में कांग्रेस नेता सुधीर चौधरी, पर्ल चौधरी, पूर्व विधायक रामबीर सिंह नाम प्रबल दावेदारों में शामिल है।

गुड़गांव-सोहना सीट पर पेंच

दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हाईकमान के बीच गठबंधन को लेकर चर्चा अंतिम दौर में है। आम आदमी पार्टी गुड़गांव सीट भी मांग रही है। इसको लेकर पेंच फंसा हुआ है। वैसे इस क्षेत्र से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, मोहित मदनलाल ग्रोवर, वरिष्ठ नेता पंकज डावर, आशीष दुआ, कुलराज कटारिया, कुलदीप कटारिया, सीमा गुप्ता आजाद, खुशबू मंगला शर्मा, गजे सिंह कबलाना, सुनीता सहरावत, डॉ. मुकेश शर्मा, सूबे सिंह यादव समेत 32 नेताओं ने दावेदारी कर रखी है।

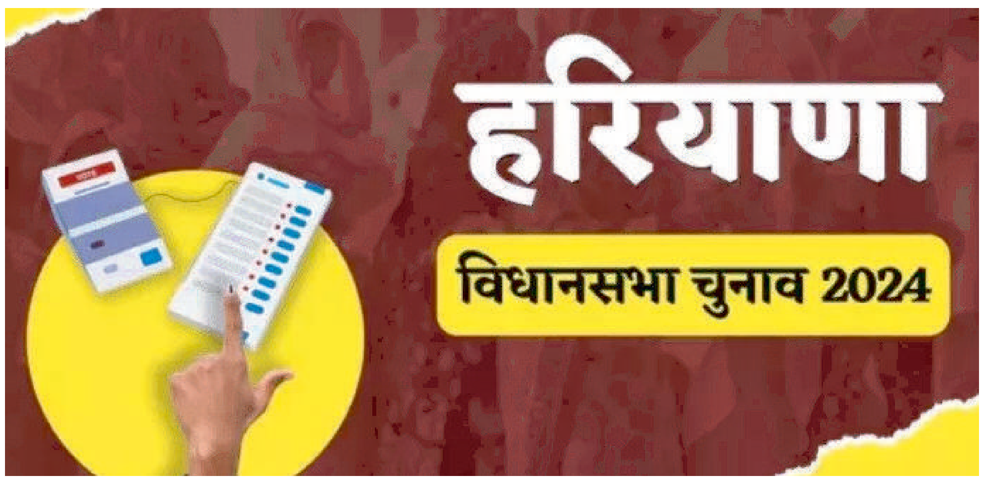

पार्टी सूत्रों के अनुसार हाईकमान पूर्व मंत्री सुखबीर कटारिया, मोहित मदनलाल ग्रोवर और वरिष्ठ नेता पंकज डावर के नाम पर विचार कर रहा है। दूसरी ओर सोहना सीट से सैलजा और हुड्डा गुट दोनों एक्टिव है। यहां से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, वरिष्ठ नेता अरिदमन सिंह बिल्लू, शमशुद्दीन और सैलजा गुट के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राव कमलवीर के बेटे राजकमल व यूथ कांग्रेस के प्रदेश सचिव कुलदीप गुर्जर टिकट के प्रबल दावेदार हैं।

मुफ्त की संस्कृति से पंजाब-हिमाचल की बढ़ी आर्थिक मुश्किलें

कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे पंजाब राज्य का राजस्व घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.99 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 3.87 फीसदी तक जा पहुंचा है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 44.12 फीसदी हो गया है।

दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों के सम्मुख वित्तीय संकट के धुंधलके छाने लगे हैं। सत्ता पर बैठी आम आदमी पार्टी एवं कांग्रेस की सरकारों के सामने चुनाव के दौरान वोटरों को लुभाने के लिए की गयी फ्रीबीज या रेवड़ी कल्चर की घोषणा आर्थिक संकट का बड़ा कारण बन रही है। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने एवं लोक-लुभावन घोषणाओं के कितने भारी नुकसान होते हैं, इस बात को दिल्ली, पंजाब व हिमाचल सरकारों के सामने खड़ी हुई वित्तीय परेशानियों से समझा जा सकता है। इन सरकारों के लगातार बढ़ते राजस्व घाटा व बड़ी होती देनदारियां राज्य की अर्थव्यवस्था पर भारी पड़ रही हैं। विकास योजनाओं को तो छोड़े, इन राज्यों में कर्मचारियों को वेतन व सेवानिवृत्त कर्मियों को समय पर पेंशन देने में मुश्किलें आ रही हैं। इन जटिल होती स्थितियों को लेकर 'रेवड़ी कल्चर' पर न्यायालय से लेकर बुद्धिजीवियों एवं राजनीति क्षेत्रों में व्यापक चर्चा है। पंजाब के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग की हालिया रिपोर्ट में राज्य की वित्तीय प्राप्तियों और खर्चे के बीच बढ़ते राजकोषीय अंतर को उजागर किया गया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुक्त की संस्कृति पर तीखे प्रहार करते हुए इसे देश के लिए नुकसानदायक परंपरा बता चुके हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने भी मुफ्त रेवड़ियां बांटने के चलन पर गंभीर चिंता जता चुके हैं। नीति आयोग के साथ रिजर्व बैंक भी मुफ्त की रेवड़ियों पर आपत्ति जता चुका है, लेकिन राजनीतिक दलों पर कोई असर नहीं है।

कैग की रिपोर्ट बताती है कि कैसे पंजाब राज्य का राजस्व घाटा, सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 1.99 फीसदी लक्ष्य के मुकाबले 3.87 फीसदी तक जा पहुंचा है। यह बेहद चिंताजनक स्थिति है कि राज्य का सार्वजनिक ऋण जीएसडीपी का 44.12 फीसदी हो गया है। यदि अब भी सत्ताधीश वित्तीय अनुशासन का पालन नहीं करते एवं मुक्त की सुविधाएं देने से बाज नहीं आते तो निश्चित ही राज्य को बड़ी मुश्किल की ओर धकेलने जैसी बात होगी। जिसका उदाहरण सामने है कि बीते माह का वेतन निर्धारित समय पर नहीं दिया जा सका है। इसके बावजूद सत्ता पर काबिज नेता मुफ्त की रेवड़ियों को बांटने का क्रम जारी रखे हुए हैं तो उसकी कीमत न केवल टैक्स देने वालों को चुकानी पड़ रही है बल्कि आम लोगों के जीवन पर भी इसका प्रतिकूल असर पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य का खर्चा जहां 13 प्रतिशत की गति से बढ़ रहा है, वहीं राजस्व प्राप्तियां 10.76 फीसदी की दर से बढ़ रही हैं। जाहिर है, ये अंतर राज्य की आर्थिक बदहाली, आर्थिक असंतुलन एवं आर्थिक अनुशासनहीनता की तस्वीर ही उकेरता है। दिल्ली से लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकारें हों या हिमाचल प्रदेश से लेकर अन्य राज्यों में कांग्रेस की सरकारें तमाम तरह की मुफ्त की रेवड़ियां बांट कर भले ही वोट बैंक को अपने पक्ष में करने का स्वार्थी खेल खेला जा रहा हो, लेकिन इससे वित्तीय बजट लडखड़ाने ने इन राज्यों के लिये गंभीर चुनौती बन रहा हैं।

दरअसल, जिस भी नागरिक सुविधा को मुफ्त किया जाता है, उस विभाग का तो भट्टा बैठ जाता है। फिर उसका आर्थिक संतुलन कभी नहीं संभल पाता। कैग की हालिया रिपोर्ट बताती है कि पंजाब में एक निर्धारित यूनिट तक मुफ्त बिजली बांटे जाने से राज्य के अस्सी फीसदी घरेलू उपभोक्ता मुफ्त की बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं। ये और ऐसी ही अन्य मुफ्त सुविधाओं की भरमार के कारण सरकारों के सामने अपने कर्मियों को समय पर वेतन देने के लिये वित्तीय संकट है, जबकि वेतन पर आश्रित कर्मियों को राशन-पानी, बच्चों की स्कूल की फीस व लोन की ईएमआई आदि समय पर चुकाने में दिक्कत हो रही है। इन जटिल होते हालातों को देखते हुए अपेक्षा है कि राजनेता सस्ती लोकप्रियता पाने के लिये सब्सिडी की राजनीति एवं मुफ्त की संस्कृति से परहेज करें और वित्तीय अनुशासन से राज्य की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का प्रयास करें। जब भी ऐसी लोक-लुभावन घोषणाएं की जाती हैं तो उन दलों को अपने घोषणापत्र में यह बात स्पष्ट करनी चाहिए कि वे जो लोकलुभावनी योजना लाने जा रहे हैं, उसके वित्तीय स्रोत क्या होंगे? कैसे व कहां से यह धन जुटाया जाएगा? साथ ही जनता को भी सोचना चाहिए कि मुफ्त के लालच में दिया गया वोट कालांतर उनके हितों पर भारी पड़ेगा। जनता को गुमराह करते हुए, उन्हें ठगते हुए देश में रेवड़ियां बांटने का वादा और फिर उन पर जैसे-तैसे और अक्सर आधे-अधूरे ढंग से अमल का दौर चलता ही रहता है। लोकलुभावन वादों को पूरा करने की लागत अंततः मतदाताओं को खासकर करदाताओं को ही वहन करनी पड़ती है-अक्सर करों अथवा उपकरों के रूप में। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के समय मुफ्त रेवड़ियां देने के मुद्दे को उठाते हुए कहा था कि कई राज्यों ने अपनी वित्तीय स्थिति की अनदेखी करते हुए मुफ्त की सुविधाएं देने का वादा कर दिया है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भी कुछ समय पहले उन दलों को आड़े हाथों लिया था, जो वोट लेने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां देने के वादे करते हैं। उनका कहना था कि रेवड़ी बांटने वाले कभी विकास के कार्यों जैसे रोड, रेल नेटवर्क आदि का निर्माण नहीं करा सकते। वे अस्पताल, स्कूल और

गरीबों के घर भी नहीं बनवा सकते। रेवड़ी संस्कृति अर्थव्यवस्था को कमजोर करने के साथ ही आने वाली पीढ़ियों के लिए घातक भी साबित होती है। इससे मुफ्तखोरी की संस्कृति जन्म लेती है। मुफ्त की सुविधाएं पाने वाले तमाम लोग अपनी आय बढ़ाने के जतन करना छोड़ देते हैं। पंजाब में महिलाओं को नगद राशि देने की घोषणा हुई, जबकि वहां की महिलाएं समृद्ध है। दिल्ली में उन महिलाओं को भी डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा दी गई है, जिन्हें इस तरह की सुविधा की जरूरत नहीं। आधी आबादी को मुफ्त यात्रा की सुविधा देने से दिल्ली में डीटीसी को हर साल 15 करोड़ रुपये तक का नुकसान होगा। इस राशि का उपयोग दिल्ली के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सकता है। मुफ्तखोरी की राजनीति से देश का आर्थिक बजट लडखड़ाने का खतरा है। और इसके साथ निषक्रियता एवं अकर्मण्यता को बल मिलेगा। हिंदुस्तान में लोगों को बहुत कम में जीवन निर्वहन करने की आदत है ऐसे में जब मुफ्त राशन, बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा मिलेगा तो काम क्यों करेंगे।

'गरीब की थाली में पुलाव आ गया है, लगता है शहर में चुनाव आ गया है' भारत की राजनीति से जुड़ी विसंगतियों एवं विडम्बनाओं पर ये दो पंक्तियां सटीक टिप्पणी हैं। चुनाव आते ही वोटरों को लुभाने के लिए जिस तरह राजनीतिक दल और उनके नेता वायदों की बरसात करते हैं, यह शासन-व्यवस्थाओं को गहन अंधेरों में धकेल देता है। मुफ्त की संस्कृति को कल्याणकारी योजना का नाम देकर राजनीतिक लाभ की रोटियां सेंकी जाती रही है। भारत जैसे विकासशील देश के लिये यह मुक्त संस्कृति एक अभिशाप बनती जा रही है। सच भी है कि मतदाताओं का एक बड़ा वर्ग आज भी इस स्थिति में है कि कथित तौर पर मुफ्त या सस्ती चीजें उसके वोट के फैसले को प्रभावित करती हैं। मुफ्त 'रेवड़ी' व कल्याणकारी योजनाओं में संतुलन कायम करना आवश्यक है, परंतु वोट खिसकने के डर से राजनीतिक दल इस बारे में मौन धारण किये रहते हैं, बल्कि न चाहते हुए भी इसे प्रोत्साहन भी देते हैं। फ्रीबीज' या मुफ्त उपहार न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में वोट बटोरने एवं राजनीतिक धरातल मजबूत करने का हथियार हैं। मुफ्त उपहार के मामले में कोई भी देश पीछे नहीं है। ब्रिटेन, इटली, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, स्वीडन, संयुक्त अरब अमीरात, बांग्लादेश, मलेशिया, कनाडा, अंगोला, कीनिया, कांगो, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया सहित अनेक देश इस दौड़ में शामिल हैं। विकसित देश जहां अपनी जीडीपी का 0.5 प्रतिशत से 1 प्रतिशत तक लोककल्याण योजनाओं में खर्च करते हैं, तो विकासशील देश जीडीपी का 3 प्रतिशत से 4 प्रतिशत तक फ्रीबीज के नाम पर खर्च कर देते हैं। भारत में अब जब न्यायालय की चौखट पर यह मुद्दा विचाराधीन है, तो संभावना है कि सरकार पर अनावश्यक आर्थिक भार डालने वाली घोषणाओं पर नियंत्रण को लेकर कोई राह भारत ही दुनिया को दिखाए।

- :सौजन्य :-
ईवी ड्राइव द फ्यूचर
EV
Drive the Future

10 सितंबर से काशी जोन में चार रूट पर चलेंगे ई-रिक्शा

परिवहन विशेष न्यूज

कमिश्नरेट के काशी जोन के आदमपुर, जैतपुरा, कोतवाली, चेतगंज, सिगरा, चौक, दशाश्वमेध, लक्सा, भेलूपुर, लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र में 10 सितंबर से ई-रिक्शा नई व्यवस्था के तहत चलेंगे। इन 11 थाना क्षेत्रों में लाल, पीले, हरे और नीले रंग के क्यूआर कोड लगाए हुए ई-रिक्शा निर्धारित चार रूट पर चलेंगे।

ट्रैफिक पुलिस लाइन स्थित सभागार में शुक्रवार को व्यापार मंडल के पदाधिकारियों, ई-रिक्शा और ऑटो यूनियन के पदाधिकारियों व चालकों के साथ पुलिस अफसरों ने बैठक की। बैठक में तय किया गया कि चार रूट आधारित व्यवस्था के लिए ट्रैफिक पुलिस लाइन में नौ सितंबर से पंजीकरण शुरू होगा। ई-रिक्शा चालक/संचालक को अपने साथ वाहन के रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और फिटनेस का कागज लेकर जाना होगा।

10 सितंबर से क्यूआर कोड वितरित होगा। 10 सितंबर से ही जिन ई-रिक्शा की फिटनेस सही नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ ट्रैफिक पुलिस कार्रवाई भी शुरू करेगी। इस दौरान अपर पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) डॉ. एस चनप्पा, डीसीपी ट्रैफिक हृदेश कुमार और एडीसीपी ट्रैफिक राजेश कुमार पांडेय मौजूद रहे।

रूट नंबर - 01-कलर कोड - लाल

कोतवाली, जैतपुरा और आदमपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा चलेंगे।

पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या - 5071

रूट नंबर - 02 - कलर कोड - पीला

चेतगंज, लक्सा, चौक, दशाश्वमेध और सिगरा थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा चलेंगे।

पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या - 3362

रूट नंबर - 03 - कलर कोड - हरा

भेलूपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा चलेंगे।

पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या - 2786

रूट नंबर - 04 - कलर कोड - नीला

लंका और चितईपुर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा चलेंगे।

पंजीकृत ई-रिक्शा की संख्या - 2507

काशी जोन के 11 थाना क्षेत्रों में वरुणा और गोमती जोन के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा नहीं जाएंगे।

रामनगर थाना क्षेत्र के पते पर पंजीकृत ई-रिक्शा नमो घाट और सामने पुल के नीचे तक ही जाएंगे।

BMW CE 02 की लॉन्च से पहले शुरू हुई बुकिंग, एक बार चार्ज करने पर चलेगी 90 किलोमीटर

परिवहन विशेष न्यूज

BMW Motorrad अपनी आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर CE 02 की बुकिंग शुरू कर दी है। कंपनी इस स्कूटर को सितंबर के आखिरी तक लॉन्च कर सकती है। BMW के इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में TFT डिस्प्ले कीलेस राइड ऑटोमैटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इलेक्ट्रिक रिवर्स गियर सिंगल-चैनल ABS और USB-C चार्जिंग जैसे फीचर्स मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह किन फीचर्स के साथ आने वाली है।

नई दिल्ली। BMW Motorrad ने अपनी आगामी इलेक्ट्रिक स्कूटर CE 02 के लिए लॉन्च करने से पहले ही बुकिंग को शुरू कर दिया है। भारत में CE 04 के बाद यह कंपनी का दूसरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है। BMW CE 02 को खरीदने का जो प्लान बना रहे हैं वह अपने नजदीकी अधिकृत BMW Motorrad डीलरशिप जाकर इसकी लॉन्च होने से पहले बुकिंग करवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि यह स्कूटर किस तारीख को भारत में एंट्री मारेगी और यह किन फीचर्स के साथ आने वाली है।

BMW CE 02: फीचर्स

BMW CE 02 के लॉन्च से पहले एक टीजर जारी किया गया है। जिसके मुताबिक इसे बेहद अट्रैक्टिव डिजाइन, मिनिमलिस्ट बॉडीवर्क, सिंगल-पीस फ्लैट सीट, एक LED हेडलैंप, एक छोटा वाइज़र और एक गोल्डन अपसाइड-डाउन (USD) फ्रंट फोर्क के साथ आने वाली है। इतना ही नहीं, इस स्कूटर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ 3.5-इंच TFT डिस्प्ले, कीलेस राइड, ऑटोमैटिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, इलेक्ट्रिक रिवर्स गियर, सिंगल-चैनल ABS और USB-C चार्जिंग जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं।

BMW CE 02: पावरट्रेन

ग्लोबल मार्केट में मिलने वाली BMW CE 02 दो रिमूवेबल बैटरी 1.96kWh के साथ आती है, जो एयर-कूल्ड सिंक्रोनस मोटर को पावर भेजती हैं। इलेक्ट्रिक स्कूटर में लगा बैटरी 15bhp और 55Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। सिंगल बैटरी के साथ स्कूटर को 45 किमी तक सफर किया जा सकता है और इसकी टॉप स्पीड 45 किमी/घंटा है। वहीं, ट्विन-बैटरी सेटअप 95 किमी/घंटा की टॉप स्पीड के साथ 90 किमी की रेंज देता है।

BMW CE 02: चार्जिंग टाइम

इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 0.9kW चार्जर से 5 घंटे और 12 मिनट में 0% से 100% तक चार्ज किया जा सकता है। वहीं, 1.5kW फास्ट चार्जर से फुल चार्ज होने में 3 घंटे और 30 मिनट तक का समय कम हो जाता है। यह देखा जा सकता है कि कंपनी भारत में इसे सिंगल- या ट्विन-बैटरी सेटअप के साथ लॉन्च करती है।

BMW CE 02: हार्डवेयर

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, भारत में लॉन्च होने वाले इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में आगे की तरफ USD फोर्क और पीछे की तरफ मोनोशॉक देखने के लिए मिलेगा, जबकि ब्रेकिंग सेटअप में 239 मिमी फ्रंट डिस्क और 220 मिमी रियर डिस्क दिया जा सकता है।

BMW CE 02: कीमत

इसे TVS के सहयोग से डेवलप किया गया BMW का पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर है। इसे इस महीने भारत में लॉन्च किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस स्कूटर की कीमत भारत में 4 लाख रुपये से 5 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) को बीच होने वाली है।

ईज़माईट्रिप ने ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी के साथ मिलकर इलेक्ट्रिक बस निर्माण की दिशा में बढ़ाया कदम

परिवहन विशेष न्यूज

भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन ट्रैवल टेक प्लेटफ़ॉर्म में से एक, ईज़माईट्रिप ने अपनी नई सहायक कंपनी ईज़ ग्रीन मोबिलिटी के ज़रिए इलेक्ट्रिक बस निर्माण बाज़ार में प्रवेश करने की घोषणा की है। ईज़ ग्रीन मोबिलिटी ईवी बसों का निर्माण करेगी, जिसमें योलोबस इसकी संचालन शाखा के रूप में काम करेगी। यह पहल पर्यावरण के अनुकूल और अभिनव यात्रा समाधान पेश करके एक नए सेगमेंट को भुनाने की ब्रांड की प्रतिबद्धता में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो टिकाऊ गतिशीलता की दिशा में अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है। ईज़माईट्रिप व्यापक शोध और विकास, उत्पाद विकास और एक विनिर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए 2-3 वर्षों की अवधि में 200 करोड़ रुपये का निवेश कर रहा है।

भारतीय इलेक्ट्रिक बस बाजार में 2024 से 2030 तक 24% की सीएजीआर से वृद्धि होने की उम्मीद है। ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी की स्थापना उभरते बाजार के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर कब्जा करने और भारत में ईवी की बढ़ती मांग का लाभ उठाने के लिए ईज़माईट्रिप के दृष्टिकोण के अनुरूप है। यह क्षेत्र के विकास को गति देने और सर्वोत्तम और अभिनव प्रौद्योगिकी समाधान प्रदान करने के लिए ब्रांड के प्रतिबद्ध दृष्टिकोण का प्रमाण है।

ईज़माईट्रिप के सीओ-फाउंडर रिकेंट पिट्टी ने कहा "अब से एक दशक बाद इलेक्ट्रिक बसों की वार्षिक मांग बढ़कर 125,000 से 150,000 यूनिट प्रति वर्ष हो जाने की उम्मीद है। मौजूदा मार्केट की डायनामिक सप्लाई बढ़ाने और प्रोडक्शन को लोकल बनाकर और पूरी तरह से 'मेक-इन-इंडिया' प्रोडक्ट बनाकर इलेक्ट्रिक बसों की बढ़ती मांग को पूरा करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रस्तुत करती है।"

उन्होंने कहा "फेम योजना, राज्य स्तरीय नीतियों और पीएलआई योजनाओं के माध्यम से सरकार पूरे देश में इलेक्ट्रिक बसों को अपनाने को प्रोत्साहित कर रही है। हमारी नई सहायक कंपनी ईज़ी ग्रीन मोबिलिटी उनके अनुकरणीय प्रयासों का समर्थन करने और ग्रीन मोबिलिटी में वैश्विक नेता बनने के भारत के दृष्टिकोण में योगदान करने का एक तरीका है। इसके अलावा यह कदम गैर-हवाई व्यवसाय का विस्तार करने की हमारी विकास योजनाओं के अनुरूप है और इससे हमें बढ़ते ईवी और ईमोबिलिटी क्षेत्र में मजबूत पैर जमाने में मदद मिलेगी।"

नई हीरो डेस्टिनी 125 का टीजर जारी, मिलेगा लंबी सीट और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी

नई दिल्ली। हीरो मोटोकॉर्प नई हीरो डेस्टिनी 125 को 9 सितंबर को लॉन्च करने जा रही है। इसे भारतीय बाजार में लॉन्च करने को लेकर कंपनी की तरफ से तैयारी भी कर ली गई है। साल 2018 में लॉन्च होने के बाद डेस्टिनी 125 स्कूटर में यह पहला बड़ा अपडेट दिया जा रहा है। हीरो मोटोकॉर्प नई Hero Destini 125 को को लॉन्च करने से पहले इसके दो टीजर जारी किया है। आइए जानते हैं कि इसमें क्या कुछ खास होने वाला है।

New Hero Destini 125: टीजर में क्या दिखा

हीरो मोटोकॉर्प की तरफ से सोशल मीडिया पर जारी किए गए दो टीजर में Hero Destini 125 के कई फीचर्स के बारे में पता चल रहा है। जिसमें सबसे बड़ा बदलाव इसका डिजाइन होने वाला है। इसमें डेटाइम रनिंग लाइट के साथ अधिक चौकोर एलईडी हेडलाइट, रिपोज़िशन किए गए फ्रंट इंडिकेटर, लंबी सीट और ब्रांज में तैयार किए गए एक्सेंट साथ एक नया डिजाइन दिया गया है।

महाराष्ट्र में लगेंगे मेगा सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन प्लांट, 1.17 लाख करोड़ रुपये का होगा निवेश

परिवहन विशेष न्यूज

महाराष्ट्र में औद्योगिक परियोजनाओं को लगातार मंजूरी दी जा रही है। महाराष्ट्र सरकार ने उद्योग विभाग की कैबिनेट उप समिति की बैठक में सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण से जुड़े चार बड़े प्रोजेक्ट पर मुहर लगाई। इन परियोजनाओं में 1.17 लाख करोड़ रुपये का निवेश होगा। साथ ही 29 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मराठवाड़ा, विदर्भ, पुणे और पनवेल में चार उच्च प्रौद्योगिकी मेगा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण में निवेश से महाराष्ट्र को ईवी क्षेत्र में अग्रणी राज्य की पहचान मिलेगी। परियोजनाएं मजबूत स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला विकसित करेंगीं। साथ ही तकनीक, नवाचार, अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देंगी। इससे सूक्ष्म-लघु और मध्यम उद्योग से जुड़े लोगों को मदद मिलेगी। साथ ही स्थानीय श्रम बल को प्रशिक्षण और कौशल विकास का मौका मिलेगा।

उन्होंने बताया कि टावर सेमीकंडक्टर कंपनी और अदाणी ग्रुप मिलकर रायगढ़ जिले के पनवेल में मेगा सेमीकंडक्टर निर्माण परियोजना शुरू करेंगे। इसमें पहले चरण में 58,763 करोड़ और दूसरे चरण में 25,184 करोड़ रुपये समेत कुल निवेश 83,947 करोड़ रुपये का निवेश होगा। इससे 15 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा।

पुणे में 12 हजार करोड़ रुपये के निवेश के साथ स्कोडा ऑटो वोक्सवैगन इंडिया एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परियोजना स्थापित की जाएगी। यह एक हजार लोगों को रोजगार देगी। वहीं छत्रपति संभाजीनगर में टोयोटा किर्लोस्कर मोटर कंपनी इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण परियोजना लगाएगी। इस परियोजना में 21,273 करोड़ रुपये का निवेश होगा और 12,000 नौकरियां मिलेगीं। ईवी के उपयोग से ग्रीनहाउस गैसों में कमी आएगी।

एयरपोर्ट अथॉरिटी के साथ टेरा चार्ज ने की पार्टनरशिप

परिवहन विशेष न्यूज

ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर कंपनी टेरा चार्ज ने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। कंपनी ने देशभर के एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग सुविधा लगाने के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ करार किया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले भोपाल एयरपोर्ट से हुई है। आपको बता दें कि कंपनी की ओर से पहली बार इस तरह की साझेदारी की गई है। इस करार के तहत देशभर के एयरपोर्ट पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग हब लगाए जाएंगे। इसकी शुरुआत भोपाल के राजाभोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हुई है।

जापानी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए भोपाल एयरपोर्ट पर 75 वर्ग मीटर के क्षेत्र में चार्जिंग सुविधा स्थापित की जाएगी, जिसके ज़रिए एक बार में 4 इलेक्ट्रिक वाहन चार्ज किए जा सकेंगे। शुरुआत में इस हब में स्लो चार्जर लगाया जाएगा। इसके अलावा 30 किलोवाट का फास्ट चार्जर भी दिया जाएगा, जो ई2व्हीलर, ई3व्हीलर और ई4व्हीलर की ज़रूरतों को पूरा करेगा।

इन पब्लिक और कमर्शियल चार्जर का इस्तेमाल 24 घंटे किया जा सकेगा। टेरा चार्ज पहली कंपनी है जिसने इस सेक्टर के लिए एएआई के साथ समझौता किया है। भोपाल के बाद अलग-अलग एयरपोर्ट पर भी चार्जिंग स्टेशन लगाए जाएंगे।

कंपनी ने 15 लाख रुपये का निवेश किया है और इसका लक्ष्य सार्वजनिक स्थानों पर चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करना है। इसके अलावा कंपनी के पास 4 और एयरपोर्ट प्रोजेक्ट हैं, जहां इस तिमाही के अंत तक चार्जिंग स्टेशन लगाए जाने हैं।

कंपनी ने अभी तक कोई खास तारीख का ऐलान नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि अगले 45-60 दिनों में चार्जिंग स्टेशन लगा दिया जाएगा। एंड्रॉयड और आईओएस यूजर टेरा चार्ज मोबाइल ऐप के जरिए चार्जिंग स्टेशन का पता लगा सकते हैं।

सब्सिडी पर खरीद रहे हैं ईवी, तो पहले वाहन के साथ खीचें फोटो

परिवहन विशेष न्यूज

केंद्र सरकार उर्वरक और कोविड टीके के प्रमाणपत्र के बाद अपनी प्रमुख इलेक्ट्रिक मोबिल्टी योजनाओं के तहत बेचे जाने वाले इलेक्ट्रिक दोपहिया और तिपहिया वाहनों पर अपनी ब्रांडिंग की योजना बना रही है। ऐसा माना जा रहा है कि केंद्र सब्सिडी योजना के तहत बेचे जाने वाले किसी भी ईवी वाहन पर मंत्रालय के लोगो के साथ ग्राहक की फोटो वाला प्रमाणपत्र जारी करने की योजना का खाका तैयार कर रही है।

इस क्रम में केंद्र जाने अपने ग्राहक को केवाईसी अनिवार्य भी कर सकती है। इसमें ग्राहक को सरकारी पोर्टल पर अपने वाहन के साथ सेल्फी फोटो अपलोड करने के साथ आधार का प्रमाणन करना पड़ सकता है। इसके बाद ही ईवी का पंजीकरण हो पाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि इस कदम का ध्येय ग्राहकों तक सरकारी सब्सिडी जारी होने का संदेश पहुंचाना है।

अधिकारियों के अनुसार 'सरकार सब्सिडी दे रही है, न कि कंपनी कोई छूट दे रही है।' दरअसल मूल उपकरण निर्माता यह पेश कर रहे हैं कि यह कंपनी ने छूट मुहैया करवाई है और इससे ग्राहकों को केंद्र सरकार की पहल की जानकारी नहीं मिल पा रही है। अधिकारियों के अनुसार सरकार ने इस चिंताजनक स्थिति के कारण कदम उठाया है।

प्रधानमंत्री कार्यालय की अध्यक्षता में हाल में हुई इस बैठक में चर्चा हुई थी। इसमें यह चर्चा हुई थी कि दो पहिया, तीन पहिया और ई-कार खरीदने वाले ग्राहकों को ईवी पर सरकारी सब्सिडी मिलने की जानकारी नहीं थी। ओईएम ऐसा प्रदर्शित कर रहे हैं कि वे कम दामों पर वाहन मुहैया करवा रहे हैं और सरकार से सब्सिडी मिलने की जानकारी को उजागर नहीं कर रहे हैं।

ई-दो पहिया और ई-तिपहिया पर फेम-2 का कोई स्टीकर भी नहीं होता है जबकि इसके विपरीत ई-बसों पर योजना फेम-2 का स्टीकर लगा होता है। ई-दुपहिया और ई-तिपहिया वाहन सरकार की कोई ब्रांडिंग भी नहीं करते हैं और वाहन के दाम कम होने के स्रोत को भी छुपाते हैं।

इस मामले के जानकार ने मीडिया को बताया, 'अभी तक ओईएम ग्राहकों को वाहन कम दाम पर मुहैया कराने को छूट के रूप में पेश कर रहे हैं। इस कदम से सरकारी योजना को लेकर पारदर्शिता बढ़ेगी।' इस बारे में भारी वाहन मंत्रालय को सवाल भेजे गए थे लेकिन खबर छपने तक कोई जवाब नहीं मिला।

उपभोक्ता को वाहन का पंजीकरण हासिल करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट या बाद में लॉन्च किए जाने वाले पोर्टल पर आधार आधारित पंजीकरण को पूरा करना होगा। इस प्रमाणपत्र पर मंत्रालय और योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी उपलब्ध होगी।

मंत्रालय की योजना ओईएम के साथ बैठक करनी है ताकि उन्हें होने वाले बदलाव के बारे में बताया जा सके। इसके अलावा ग्राहकों के वाहनों के पंजीकरण और वाउचर के लिए डीलर की मदद लेना है। ग्राहक को प्रमाणपत्र हासिल करने के बाद वाहन के साथ फोटो खींचनी होगी और फिर पंजीकरण प्रक्रिया के हिस्से के रूप में इस फोटो मंत्रालय के पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। इस कदम से यह प्रमाण मिलेगा कि ग्राहकों को लाभ मिला है। वाउचर का पंजीकरण ग्राहक की उपस्थिति या ग्राहक स्वयं करेगा।

अन्य अधिकारी ने बताया, 'ग्राहक के वाहन के साथ फोटो खींचने के बाद ही वाहन की पंजीकरण की प्रक्रिया पूरी होगी। इस कदम से यह सुनिश्चित हो पाएगा कि ग्राहकों को वास्तविकता में वाहन प्राप्त हुआ है और वाउचर का पंजीकरण ग्राहक स्वयं करेगा या उसकी उपस्थिति में किया जाएगा।'

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल को अनलॉक करना

विजय गर्ग

सामाजिक कार्य में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अपेक्षाकृत एक उभरता हुआ अनुप्रयोग क्षेत्र है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में कंप्यूटर सिस्टम को उन कार्यों को करने में सक्षम बनाकर हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता है, जिनके लिए सामान्य रूप से मानव बुद्धि की आवश्यकता होती है, जैसे तर्क, समस्या-समाधान, अनुभव-आधारित शिक्षा और प्राकृतिक भाषा समझ। कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और सामाजिक कार्य के अभिसरण से तकनीकी परिवर्तन के एक नए युग का नेतृत्व किया जा रहा है, जिसमें समाज के सबसे कमजोर सदस्यों को सामाजिक सेवाएं प्रदान करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने का वादा किया गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) में अपने पूर्वानुमानित विश्लेषण, मशीन लर्निंग और प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण क्षमताओं के माध्यम से सेवा वितरण, दक्षता में सुधार और जरूरतमंद व्यक्तियों को व्यक्तिगत सहायता प्रदान करने का बड़ा वादा है। सामाजिक कार्य पेशे में हस्तक्षेप के लिए एआई की संभावनाएं सामाजिक कार्यों में एआई का अनुप्रयोग सेवा वितरण की सटीकता, दक्षता और सहानुभूति में सुधार के लिए संभावनाओं की एक विस्तृत श्रृंखला खोलता है। सामाजिक कार्यकर्ता एआई की क्षमताओं का उपयोग करके कमजोर आबादी के लिए अधिक व्यक्तिगत, केंद्रित और सफल हस्तक्षेप की पेशकश कर सकते हैं। एआई-संचालित भविष्य कहनेवाला स्वास्थ्य निगरानी उन वरिष्ठ नागरिकों की सहायता करने के तरीके को पूरी तरह से बदलने की क्षमता रखती है जो स्वास्थ्य समस्याओं के जोखिम में हैं। एआई एल्गोरिदम रुझानों और प्रारंभिक चेतावनी संकेतों को पहचानने में सक्षम हैं जो पहनने योग्य प्रौद्योगिकी, चिकित्सा रिकॉर्ड और अन्य स्रोतों से भारी मात्रा में डेटा का मूल्यांकन करके संभावित स्वास्थ्य समस्या की ओर इशारा कर सकते हैं। इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना, संकट उत्पन्न होने से पहले त्वरित हस्तक्षेप और सहायता प्रदान करना संभव हो जाता है। इस सक्रिय, डेटा-संचालित दृष्टिकोण से वरिष्ठ नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता को काफी बढ़ाया जा सकता है, जो स्वास्थ्य देखभाल प्रणालियों पर तनाव को भी कम कर सकता है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए एआई-संचालित उपचारों को समूहों की अनूठी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अनुकूलित किया जा सकता है। स्व-रिपोर्ट किए गए लक्षणों, थेरेपी सत्र नोट्स और बायोमेट्रिक डेटा सहित कई स्रोतों से डेटा की जांच करके, डॉक्टर रुझानों और विशिष्ट विशेषताओं को खोजने के लिए एआई एल्गोरिदम का उपयोग कर सकते हैं जो व्यक्तिगत उपचार दृष्टिकोण को सूचित कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता ग्राहकों की बेहतर मदद कर सकते हैं, बायोमेडिकल डोमेन में एआई की उपयोगिता के बारे में लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए आउटरीच कार्यक्रम चला सकते हैं और उनकी आवश्यकताओं के लिए विशिष्ट मान्यता प्राप्त पैटर्न के आधार पर उपचार को अनुकूलित करके बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, प्रत्येक बच्चे की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप व्यक्तिगत शिक्षण अनुभव प्रदान करके, भावना पहचान जैसी एआई तकनीकें ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम पर बच्चों के लिए शैक्षिक परिणामों को काफी बढ़ा सकती हैं। जो बच्चे न्यूरोडायवर्जेंट होते हैं उन्हें अक्सर संचार, सामाजिक संपर्क और भावनात्मक विनियमन में कठिनाइयां होती हैं, जो उनकी सीखने और बढ़ने की क्षमता में बाधा डालती है। फिर भी, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक एआई-संचालित भावना पहचान सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बच्चे की भावनात्मक स्थिति के बारे में प्राप्त उपयोगी जानकारी के आधार पर अपनी शिक्षण रणनीतियों को संशोधित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति पर विचार करें जब एआई सिस्टम सीखने की गतिविधि पर काम कर रहे ऑटिज्म से पीड़ित एक युवा में निराशा या चिंता के संकेतक देखता है। शिक्षक तब कर सकता हैसुखदायक या प्रतिक्रियाशील तंत्र का उपयोग करके या चिंता या हताशा की ओर संकेत करने वाली असामान्यता का संकेत देने वाले सिस्टम के साथ बाधा को दूर करने में युवाओं की मदद करने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करके प्रतिक्रिया दें। एआई प्रणाली एक वैयक्तिकृत शिक्षण योजना विकसित कर सकती है जो समय के साथ बच्चे की अपनी आदतों और प्राथमिकताओं के बारे में सीखकर उसकी संलग्नता और प्रगति को अधिकतम करती है। सभी बच्चे शैक्षिक वातावरण में फल-फूल सकते हैं और इस अनुकूलित दृष्टिकोण के समर्थन से जीवन में सफलता के लिए आवश्यक कौशल हासिल कर सकते हैं। ये उदाहरण दिखाते हैं कि सामाजिक कार्यों में एआई को शामिल करने से हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने और उनकी सहायता करने के तरीके में क्रांति लाने की क्षमता है। सामाजिक कार्यकर्ता अधिक सटीक, सहानुभूतिपूर्ण और प्रभावी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जो वास्तव में डेटा और उन्नत विश्लेषण का उपयोग करके लोगों के जीवन को बेहतर बनाते हैं। समकालीन युग में अनुप्रयोग सामाजिक कार्यों में एआई का जबरदस्त प्रभाव उन क्षेत्रों की विस्तृत श्रृंखला से प्रदर्शित होता है जिनमें इसे व्यवहार में लागू किया जाता है। सफलता का एक क्षेत्र बेघर होने की रोकथाम है। सामाजिक कार्यकर्ता एआई-संचालित भविष्य कहनेवाला विश्लेषण का उपयोग करके उन व्यक्तियों और परिवारों की पहचान कर सकते हैं जो बेघर होने के खतरे में हैं, जो उन्हें शीघ्र हस्तक्षेप करने और अनुरूप सहायता प्रदान करने में सक्षम बनाता है। इसी तरह, एआई का उपयोग संभावित मानसिक स्वास्थ्य आपात स्थितियों की पहचान करने, निवारक हस्तक्षेप की अनुमति देने और यह गारंटी देने के लिए किया जा सकता है कि जो लोग जोखिम में हैं उन्हें शीघ्र और कुशल सहायता मिले। पेशेवरों के लिए नैतिक चुनौतियाँ डिजिटल अंतर, गोपनीयता संबंधी चिंताएं, डेटा पहुंच और नैतिक उलझनें कुछ ऐसी बाधाएं हैं जिनका सामना एआई को अपनी क्षमता के बावजूद सामाजिक कार्यों में शामिल करने में करना पड़ता है। गोपनीयता की रक्षा करना, पूर्वाग्रह से बचना, मानवीय निगरानी बनाए रखना और सामाजिक कार्यकर्ताओं के बीच डिजिटल साक्षरता को बढ़ावा देना एआई का नैतिक रूप से उपयोग करने के लिए आवश्यक है। एआई की सफल तैनाती पारदर्शी और विविध डेटा सेटों का उपयोग करके, संवेदनशील जानकारी को अज्ञात बनाकर और सभी एआई कार्यान्वयन में आवश्यक मानवीय तत्व को बनाए रखकर इन मुद्दों को संबोधित करने पर निर्भर करती है। व्यावसायिकता और सहानुभूति को बरकरार रखते हुए सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्रौद्योगिकी का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए, उन्हें यह भी सिखाया जाना चाहिए कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता द्वारा प्रदान की गई अंतर्दृष्टि को कैसे समझें और उसका मूल्यांकन करें। ऐसे एआई सिस्टम बनाने के लिए जो नैतिक, उद्देश्यपूर्ण और सामाजिक कार्य मूल्यों और मानवाधिकार सिद्धांतों के अनुरूप हों, समुदायों, तकनीकी इंजीनियरों और सामाजिक कार्य पेशेवरों को एक साथ काम करना चाहिए। छात्रों को तकनीकी वातावरण में सफल होने के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने के लिए, सामाजिक कार्य संस्थानों को अपने पाठ्यक्रम में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए भी अधिक प्रयास करना चाहिए। भविष्य में सामाजिक कार्यों में एआई की भूमिका सामाजिक कार्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य उज्ज्वल है। हम समुदायों की विशेष आवश्यकताओं के अनुकूल अधिक रचनात्मक समाधान विकसित करने की आशा कर सकते हैं। एआई सिस्टम बनाने के लिए कंप्यूटर वैज्ञानिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य विशेषज्ञों का एक साथ काम करना आवश्यक होगा जो न केवल तकनीकी रूप से अत्याधुनिक हों बल्कि नैतिक और सामाजिक रूप से भी स्वीकार्य हों। एआई के साथ समुदाय-आधारित उपचार को बढ़ाना अन्वेषण का एक आशाजनक क्षेत्र है। विकासशील सामाजिक चुनौतियों की पहचान करने और केंद्रित समाधानों के निर्माण का मार्गदर्शन करने के लिए एआई सोशल मीडिया, सार्वजनिक रिकॉर्ड और सामुदायिक मंचों सहित विभिन्न स्रोतों से डेटा का विश्लेषण कर सकता है। यह संयोजन में पूर्वानुमानित, वर्णनात्मक और अनुदेशात्मक विश्लेषण के उपयोग के माध्यम से किया जाता है। यह होने जैसा हैएक क्रिस्टल बॉल जब हम एनालिटिक्स और एल्गोरिदम को मापने के लिए एआई का उपयोग करते हैं क्योंकि यह हमें अतीत और वर्तमान तथ्यों के आधार पर भविष्य की भविष्यवाणी करने देता है। यह एआई के सबसेट में निहित विभिन्न विशेष एल्गोरिदम जैसे मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का उपयोग करके किया जा सकता है। चिकित्सा क्षेत्र में एआई की उपयोगिता की खोज ने विभिन्न आयामों में कई रास्ते तलाशे हैं, जिनमें से कुछ हैंः कैंसर का पता लगाना और वर्गीकरण, मस्तिष्क ट्यूमर का पता लगाना, चेहरे और शरीर के संकेतों से संबंधित विभिन्न प्रकार के डेटासेट का उपयोग करके भावना विश्लेषण, मधुमेह का पता लगाना और प्रकार का वर्गीकरण।. एक सामाजिक कार्यकर्ता का प्रमुख काम वैश्विक समुदाय तक पहुंचना है, यह बताना है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में भी एआई की भूमिका कैसे महत्वपूर्ण है, और लोगों को उपचार प्लेटफार्मों के नए तरीके अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। आधुनिक युग में, विशेष रूप से कम्प्यूटेशनल जीव विज्ञान के क्षेत्र में, एक विशिष्ट प्रकार की बीमारी या विकार से पीड़ित रोगियों के लिए अनुकूलित दवा बनाई जाती है और जीन उत्परिवर्तन के पैटर्न का अध्ययन करके उसके अनुसार दवा बनाई जाती है। यह अध्ययन विभिन्न एआई आधारित एल्गोरिदम का उपयोग करके भी आयोजित किया जाता है जहां मशीन पैटर्न सीखने और विचारोत्तेजक परिणाम और सिफारिशें देने की कोशिश करती है। इस मामले में सामाजिक कार्यकर्ताओं की आवश्यकता यह है कि चूंकि एआई डेटा-संचालित है इसलिए यदि सामाजिक कार्यकर्ता आम लोगों को अपने जैविक डेटा को साझा करने की सुविधा प्रदान कर सकते हैं या जागरूक कर सकते हैं, तो एआई एक वरदान हो सकता है और चिकित्सा क्षेत्र में क्रांति ला सकता है। आधुनिक प्रथाओं में, निर्णय लेने के लिए सामाजिक कार्यों में एआई का तेजी से उपयोग किया जा रहा है। पेशेवरों को अपने दैनिक अभ्यास में इसकी ताकत, चुनौतियों और नैतिक निहितार्थों को समझने के लिए अनुकूलित एआई शिक्षा की आवश्यकता है। कुछ मामलों में, यह देखा गया है कि एआई-सहायता प्राप्त बाल कल्याण निर्णय लेने वाले इंटरफेस का उद्देश्य सामाजिक कार्यकर्ताओं की जोखिम स्कोर को समझने, प्रासंगिक ज्ञान को शामिल करने और जटिल सामाजिक संदर्भों में मूलभूत चिंताओं को संबोधित करने की क्षमता को बढ़ाना है। सामाजिक कार्यों में एआई की क्षमता को अनलॉक करने के लिए यह समझने की आवश्यकता है कि संबंधित चुनौतियों का समाधान करते हुए सामाजिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एआई प्रौद्योगिकियों का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे किया जा सकता है। सामाजिक कार्यकर्ता डेटा-संचालित उपचार बना सकते हैं जो विशेष रूप से एक समुदाय की आवश्यकताओं के लिए अनुकूलित होते हैं और एलएलएम को निर्देशात्मक एल्गोरिदम और भविष्य कहनेवाला विश्लेषण जैसे अन्य एआई दृष्टिकोणों के साथ जोड़कर उभरती सामाजिक चिंताओं में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। भविष्य में, एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जिसमें सामाजिक कार्यकर्ता नियमित रूप से स्थानीय डेटा में पैटर्न का मूल्यांकन करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) का उपयोग करके किशोर अपराध या युवा अलगाव के उच्च जोखिम वाले समुदायों की पहचान करते हैं। इस विश्लेषण के आधार पर, वे दो समस्याओं से निपटने के लिए केंद्रित पहल कर सकते हैं। युवाओं के अलगाव के जवाब में, वे युवाओं को फिर से शामिल करने और परिवारों की सहायता करने के लक्ष्य के साथ मेंटरशिप कार्यक्रम, परिवार सहायता सेवाएं और स्कूल के बाद क्लब स्थापित कर सकते हैं। वे अपराध की रोकथाम के लिए समुदाय-आधारित हस्तक्षेप के उदाहरण के रूप में पड़ोस निगरानी कार्यक्रम, युवा डायवर्जन कार्यक्रम और स्थानीय कानून प्रवर्तन के साथ सहयोग को व्यवहार में ला सकते हैं। ये पहल सामुदायिक एकजुटता में सुधार कर सकती हैं, अपराध दर कम कर सकती हैं और दीर्घकालिक सामाजिक अलगाव को रोक सकती हैं। जैसे-जैसे एआई विकसित होता है, सामाजिक कार्यकर्ता अत्यधिक वैयक्तिकृत उपचारों को सक्षम करते हुए, भविष्य कहनेवाला विश्लेषण के माध्यम से विशिष्ट युवा लोगों की पहचान करने में सक्षम हो सकते हैं, जो अपराध या अलगाव के जोखिम में हैं। आभासी और संवर्धित वास्तविकता जैसी तकनीकों का उपयोग सकारात्मकता को प्रोत्साहित करने वाले गहन, मनोरम अनुभव बनाने के लिए किया जा सकता हैव्यवहार और महत्वपूर्ण जीवन कौशल प्रदान करना। सामाजिक पेशेवर किशोरों और परिवारों को चौबीसों घंटे समर्थन और दिशा प्रदान करने के लिए एआई-संचालित चैटबॉट और आभासी सहायकों के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, यह गारंटी देते हुए कि जरूरत पड़ने पर सहायता हमेशा सुलभ है। एआई का यह अभिनव उपयोग दिखाता है कि कैसे सामाजिक कार्य हस्तक्षेप प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पूर्व-खाली और अनुकूलित हो सकता है, अंततः बेहतर सार्वजनिक सुरक्षा, कल्याण और रचनात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकता है। सामाजिक समस्याओं को रोकने के अलावा, एआई और सामाजिक कार्य का भविष्य लोगों और समुदायों को नए और रचनात्मक तरीकों से समृद्ध होने में सक्षम बनाने पर केंद्रित होगा। एआई और सामाजिक कार्य मिलकर सेवा वितरण में क्रांति लाने और हाशिए पर रहने वाले समुदायों को सशक्त बनाने का जीवन में एक बार मिलने वाला मौका प्रदान करते हैं। सामाजिक कार्य एआई की क्षमता को अपनाकर और समाज के सबसे कमजोर सदस्यों पर इसके प्रभाव को बढ़ाने के लिए इसके नैतिक परिदृश्य को सावधानीपूर्वक नेविगेट करके प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग कर सकता है। जैसे-जैसे हम आगे बढ़ते हैं, यह महत्वपूर्ण है कि हम नैतिक व्यवहार को प्राथमिकता दें, बातचीत जारी रखें और एक नवीन संस्कृति विकसित करें। एआई का यह रचनात्मक अनुप्रयोग दर्शाता है कि कैसे सामाजिक कार्य हस्तक्षेप सक्रिय हो सकते हैं और प्रत्येक समुदाय की विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुरूप हो सकते हैं, अंततः बढ़ी हुई सार्वजनिक सुरक्षा, भलाई और सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा दे सकते हैं। सामाजिक कार्य और एआई का भविष्य न केवल सामाजिक समस्याओं को टालने के बारे में होगा, बल्कि व्यक्तियों और समुदायों को नए और नवोन्मेषी तरीकों से आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाने के बारे में भी होगा। साथ में, सामाजिक कार्य और एआई जीवन में एक बार सेवा वितरण को बदलने और वंचित समूहों की आवाज को मजबूत करने का अवसर प्रदान करते हैं। एआई की क्षमता को अपनाने और इसके नैतिक क्षेत्र को ठीक से नेविगेट करके, सामाजिक कार्य प्रौद्योगिकी का अधिक उपयोग कर सकता है और समाज के सबसे कमजोर नागरिकों पर अपना प्रभाव बढ़ा सकता है।

सेवानिवृत्तप्रधानाचार्यशैक्षिकस्तंभकार मलोट पंजाब

समस्या की जड़ तक कोई भी राजनीतिक दल और सरकारें नहीं जाना चाहती। ऐसा नहीं है कि समस्याओं का स्थायी समाधान नहीं हो सकता, किन्तु वहां तक पहुंचने और व्यावहारिक समाधान ढूंढने में पापड़ बेलने पड़ते हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने महिला चिकित्सक से बलात्कार के बाद हत्या के मामले में वही किया है जो अब तक ऐसे मामलों में दूसरे राज्य या केंद्र सरकार करती रही हैं।

कविता

संजौली विवाद की वजह

आबादी के घनत्व में फैलता शिमला शिकायत करता है या इस तारीख पर धर्म की मंजिलें गुनहगार हैं। शिमला मस्जिद विवाद हर तरह की तहजीब पर प्रश्न उठा रहा है। कानून के गोरे काले ढूंढ कर वैमनस्य का उद्गार कर रहा है। सैकड़ों आवाजें उठ खड़ी हुईं और जय-विजय के उद्घोष में कानून की आंतडियों का मुआयना कई दिशाओं में शोर सुनने लगा। एक अवैध निर्माण के माले पर आकर अगर सांसद असदुद्दीन ओवैसी बैठ जाए, तो फिर विवाद नहीं, यह टकराव हो सकता है। संजौली के हिस्से में न धर्म की आंख और न ही अवैध निर्माण की लगाम आई और यह चिंता का विषय है। यहां पाप-पुण्य का फैसला धर्म कतई नहीं कर सकता, बल्कि गुनाहों का बद किरदार या तो नगर निगम शिमला की करतूतों में छिपा है या शहरी विकास की आचार संहिता में इतने छेद हैं कि वर्षों से जारी अवैध निर्माण की परिपाटी किसी को नजर नहीं आई। अब अगर दो समुदायों के बीच टकराव जैसे हालात पैदा किए जा रहे हैं, तो सत्ता को भी कानून के रास्ते बुलंद करने पड़ेंगे। सरकार के एक मंत्री बेशक जन सैलाब की नुमाइंदगी में इंगित हुआ है, लेकिन मस्जिद पर अगर अनैतिक सीमेंट चढ़ा है, तो उसके लिए व्यवस्था ही जिम्मेदार मानी जाएगी।

ऐसे में टीसीपी महोदय किन फाइलों में गुम रहे या नगर निगम चुनावों में हार-जीत गिनने वाले चेहरे क्यों गौण हुए। यह निर्माण उस समय ही क्यों नजर आया जब दो समुदायों के बीच झड़प हुई या जब आंदोलित संवेदना सडक़ पर आई, तो ही व्यवस्था क्यों होश में आई। वैसे बेहोशी के आलम में हिमाचल की कई गलियां सो रही हैं और कहीं दबाव और कहीं प्रभाव से अवैध निर्माण जारी है। शिमला विवाद का हल न धार्मिक संगठन और न ही ओवैसी जैसे सांसद कर सकते और अगर यह दस्तूर बन गया, तो हिमाचल में ऐसे कई निशान, धार्मिक स्थान व इल्जाम हैं जो अग्रिम मोर्चे पर आ जाएंगे। अगर 34 शहरी विकास योजनाओं में से ग्यारह अर्थहीन हो गई हैं, तो समझ लेना चाहिए कि अतिक्रमण के नीचे बारूद खड़ा है। नगर नियोजन विभाग को विभिन्न सरकारों और माननीयों के राजनीतिक व्यवहार ने सजा दी है। प्रदेश में कुछ शहरी निकायों की जद में आ रहे गांवों को टीसीपी के तहत लाने की कोशिशों को खुर्द-बुर्द करने की दलीलें, अगर विधायक दे रहे हैं, तो भविष्य के खतरे ऐसे सोच के कांटों पे उगे हैं। प्रदेश सरकार को यह साबित करना होगा कि मस्जिद की लंबाई-चौड़ाई में धर्म की आड़ छुपी है या नगर निगम की नजरअंदाजी ने खता की है। जो भी हो, हिमाचल के माहौल में ऐसी तल्खियों की गुंजाइश नहीं है और न ही ओवैसी को जवाब देने का तर्क पैदा होता है। हिमाचल में मजहब से ऊपर तहजीब के आदर्श और शांति की परंपराएं निवास करती हैं। यहां का लोकतांत्रिक आचरण धर्म के पैबंद नहीं ओढ़ता, बल्कि हर चुनाव में व्यवस्था के प्रश्न गूंजते हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री की ओर से दिया गया आश्वासन कम से कम प्रदेश की चिंता में शरीक होकर, अमन की दुहाई दे रहा है। भले ही सरकार के एक मंत्री की भूमिका का आकार बड़ा व उनकी प्रशंसा का दायरा और भी बड़ा हो रहा है, लेकिन देखना यह है कि ऐसे अतिक्रमण पर कानून के हथौड़े कितने मजबूत और प्रभावशाली होते हैं।

बदतर आर्थिकी सुधारने को बड़े कदमों की जरूरत

राकेश शर्मा

जनता की मानसिकता सरकार को कुछ देने की नहीं, बल्कि सरकार से किसी न किसी जरिए से कुछ हासिल करने की बन चुकी है। जनता की इस मानसिकता को एकदम से बदलना कदापि संभव नहीं है और जब तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं होता, तब तक इस आर्थिक संकट से मुक्ति संभव नहीं है। इस समय हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद और ऋण का अनुपात 40 प्रतिशत के लगभग है। यह अनुपात प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है'

हिमाचल प्रदेश की आर्थिक बदहाली की तस्वीर आज किसी से छुपी नहीं है। आज ये पहाड़ी प्रदेश अपने इतिहास के सबसे मुश्किल आर्थिक दौर से गुजर रहा है और वर्तमान सरकार कुछ नए प्रयोगों के दम पर इस स्थिति से निपटने की कोशिश में लगी हुई है। सरकार के इन प्रयासों से प्रदेश की आर्थिकी को कितना बल मिलता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि हालात जिस कद्र बिगड़ चुके हैं उनको सुधारने के लिए छोटे-मोटे नहीं, बल्कि कुछ बड़े और कड़े प्रयास करने की आवश्यकता है। लेकिन इन बड़े प्रयासों के लिए जिस तरह की राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत होती है, उसका प्रयोग शायद कोई भी राजनीतिक दल नहीं करना चाहेगा, क्योंकि उनको पांच साल के बाद फिर से जनता के दरबार में जाना होता है और कड़े निर्णय जनता के गले आसानी से नहीं उतरते। लोकतंत्र की ये खूबसूरती है कि जनता अपनी भलाई के लिए ही सरकारों को चुनती है और सरकार अपनी नीतियों से जनता को पेश आ रही समस्याओं को दूर करने का प्रयास करती है। इन नीतियों से जब समस्या हल नहीं होती, तो इस नीति का पुनरावलोकन करने की बजाय एक नया तरीका ढूंढ लिया जाता है और वो है फ्रीबीज। अर्थात मुफ्त में जनता को वस्तु या सेवा उपलब्ध करवाना। इस कारण से जनता की मानसिकता सरकार को कुछ देने की नहीं, बल्कि सरकार से किसी न किसी जरिए से कुछ हासिल करने की बन चुकी है। जनता की इस मानसिकता को एकदम से बदलना कदापि संभव नहीं है और जब

तक इस मानसिकता में बदलाव नहीं होता, तब तक इस आर्थिक संकट से मुक्ति संभव नहीं है। इस समय हिमाचल प्रदेश का सकल घरेलू उत्पाद और ऋ्ण का अनुपात 40 प्रतिशत के लगभग है। ये अनुपात प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है। यहां पर इस बात पर ध्यान देना जरूरी है कि ये इतनी बड़ी आर्थिक समस्या कोई रातों रात पैदा नहीं हुई, बल्कि ये एक लंबे समय तक हुए आर्थिक कुप्रबंधन का परिणाम है। फ्रीबीज और लोकलुभावन निर्णयों को आधार बनाकर की गई वोट की राजनीति ही इसका मुख्य कारण रहा है। पिछले लगभग डेढ़ दशक से ये मुद्दा प्रदेश में एक बड़ी चर्चा का विषय रहा है, लेकिन कभी भी इस आर्थिक बदहाली से निपटने के लिए कोई पुख्ता पहल नहीं की गई। इस दौरान जितने भी चुनाव प्रदेश में हुए, उनमें हर विपक्षी पार्टी ने सताधारी दल पर आक्रमण करने के लिए इस मुद्दे को एक चुनावी हथियार की तरह प्रयोग किया। ये समस्या इसलिए और ज्यादा गंभीर बन गई, क्योंकि ये मुद्दा केवल और केवल एक चुनावी मुद्दा ही बन कर रह गया और कभी भी सरकारों के एजेंडे का हिस्सा नहीं बन सका। आज से पहले प्रदेश की आर्थिक बदहाली के आंकड़े जब जनता के सामने आते थे, इन आंकड़ों के प्रति जनता का ज्यादा सरोकार नहीं होता था, क्योंकि उनको लगता था कि इन आंकड़ों की अहमियत केवल कागजों और सरकारी फाइलों तक ही है।

लेकिन अब उन आंकड़ों ने अपना असर धरातल पर दिखाना शुरू कर दिया है और प्रदेश की इस आर्थिक बदहाली को प्रदेश का एक आम नागरिक भी महसूस करने लगा है। बात चाहे डिपुओं में मिलने वाले राशन में होने बाली कटौती की हो या फिर सरकारी कार्यालयों को बंद या स्थानांतरित करने की या फिर बिजली की फ्री यूनिट में कटौती की या फिर घरेलू पानी के बिल की शुरुआत करने की, ये सारे कदम प्रदेश की वित्तीय दुर्दशा का ही परिणाम हैं। इस तरह की सभी लोकलुभावन सौगातें जब जनता को दी जाती हैं, तो ये राजनीतिक दलों के प्रति सकारात्मक मनोभाव बनाने में सफल हों या ना हों, लेकिन जब इन सौगातों पर रोक लगाई जाती है, तो ये निर्णय सरकारों के प्रति एक नकारात्मक मनोभाव जरूर तैयार करते हैं। प्रदेश की कमजोर आर्थिकी यूं तो अब एक सदाबहार विषय बन चुका है, लेकिन पिछले दिनों यह विषय उस समय एकाएक चर्चा में आ गया जब हिमाचल प्रदेश के सचिवालय के कर्मचारियों द्वारा अपने महंगाई भत्ते और छठे वेतन आयोग की बकाया राशि मांग को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में अपनी मांगों के साथ- साथ कर्मचारी नेताओं द्वारा, सरकार द्वारा किए जा रहे कुछ खर्चों और नेताओं और अधिकारियों द्वारा लिए जा रहे भत्तों पर भी अंगुली उठाई गई। इस वजह से अब इन कर्मचारियों और सरकार के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री द्वारा अपने मंत्रियों और मुख्य संसदीय सचिवों के दो महीने के वेतन को भी विलंबित कर दिया गया है। यह सही है कि कर्मचारियों को अपनी मांगें सरकार के सामने रखने का पूरा अधिकार होता है और ये मांगें काफी हद तक जायज भी हैं।

सचिवालय कर्मचारियों द्वारा किए गए इस प्रदर्शन के बाद पूरे प्रदेश का कर्मचारी भी इन मांगों के प्रति गंभीर भी हुआ है, लेकिन प्रदेश की कमजोर वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए सभी पक्षों को सकारात्मकता के साथ आगे बढऩे की जरूरत है। टकराव से इस समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता है। हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने में प्रदेश के कर्मचारियों का योगदान काफी अहम रहा है। उनके इस योगदान को देखते हुए ही सरकार द्वारा अपने चुनावी वायदे के अनुसार प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन की बहाली की गई। निश्चित तौर पर ये एक बड़ा कदम सरकार द्वारा कर्मचारियों के हित में उठाया गया था। प्रदेश के कर्मचारियों सहित सभी वर्गों के विकास से ही एक सशक्त और आत्मनिर्भर हिमाचल का निर्माण संभव है और इसके लिए सभी को मिलकर और सद्भाव से कार्य करने की आवश्यकता है।

छिलकों की छाबड़ी : सरकार कड़े कदम उठा रही है

सरकार के कदमों पर सबकी नजर रहती है। पब्लिक की नजर भी रहती है और विपक्ष की नजर भी रहती है। सत्ता में जो लोग हाशिये पर बैठे होते हैं, उनकी तो सबसे ज्यादा तेज नजर अपनी ही सरकार के कदमों पर रहती है। वे इस ताक में रहते हैं कि सरकार के कदम जब डगमगाएंगे तो उन्हें हाशिये से मुख्य धारा में आने का मौका मिल जाएगा। सरकार के कदम फिसलते ही उनकी बांछें खिलने लगती हैं। विपक्ष के तो दोनों हाथों में लड्डू आ जाते हैं। चैनल वालों को परोसने के लिए नया मसाला मिल जाता है। पब्लिक भी बैठे-बैठे स्वाद लेने लगती है। अब सरकार के कदम भी कई तरह के होते हैं। बहके कदम, दिशाहीन कदम, नरम कदम और कड़े कदम। जो सरकार कदम नहीं उठाती, सुस्त लेटी रहती है, अलसाती रहती है, उसे लोग सरकार की श्रेणी में ही नहीं रखते। सरकार को अपना अस्तित्व दिखाने के लिए कोई न कोई कदम उठाने ही पड़ते हैं। यही कुछ वर्तमान हुकूमत के बारे में भी देखने को मिल रहा है। सरकार मजबूत है, लेकिन मजबूर है और मजबूरी में कड़े कदम उठा रही है। पहले नरम कदम उठा रही थी और उससे पब्लिक में चर्चा शुरू हो गई थी कि आखिर सूबे में सरकार नाम की कोई चीज है भी या नहीं। सिरफिरे लोग सरकार पर तंज कसने लगे थे। कहने लगे थे कि सरकार बहुत कोमल और नाजुक है। अपनी हड्डी पर मोच नहीं आने देना चाहती, इसलिए नरम कदम उठा रही है। यानी हरी-हरी कोमल घास पर चल रही है। और प्रदेश को चारागाह बना दिया है। सरकार चल रही है, लेकिन सरकार में शामिल चंद लोग घास को चर रहे हैं। इससे घास के अस्तित्व पर संकट खड़ा हो जाएगा। जब पब्लिक के बीच सरकार के नरम कदमों को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं तो सरकार ने कठोर कदम उठाने का निर्णय लिया। हुकूमत में एकदम से कडक़ फैसले लिए जाने लगे। एक से बढक़र एक कडक़ और कठोर फैसले। कईयों की सिट्टी-पिट्टी गुम हो गई। कईयों को सैलरी के लाले पड़ गए। कईयों की पेंशन कछुए की चाल चलने लगी। बैंक खाते में पेंशन आने की कोई निश्चित तारीख नहीं रही। इसलिए नहीं रही, क्योंकि सरकार ने कठोर कदम उठाना शुरू कर दिए थे। महंगाई भत्ते की किस्तों और एरियर पर कैंची चलने लगी।

इसलिए चलने लगी, क्योंकि सरकार कठोर निर्णय ले रही थी। जिनकी जेब पर कैंची चल रही थी, उन्होंने शोर मचाना शुरू कर दिया। उन्होंने सरकार पर ठीकरा फोडऩा शुरू कर दिया। आरोप लगाना शुरू कर दिए कि एक तरफ सरकार ने अपने लोगों को पद बांट कर खजाना लुटाना शुरू कर दिया है और उन्हें गाड़ी, बंगला, नौकर जाकर सब सुविधा प्रदान कर दी है। जबकि दूसरी तरफ आम आदमी की सुविधाओं में लगातार कटौती की जा रही है। अपने ही फैसले पलटे जा रहे हैं। अपनी ही गारंटियों से सरकार पीछे हट रही है। पिछली सरकारों ने जो सुविधाएं दी थी, वे बंद की जा रही हैं। संस्थान बंद किए जा रहे हैं। इसलिए किए जा रहे हैं क्योंकि सरकार कड़े कदम उठा रही है और कडक़ फैसले ले रही है। अगर टमाटर के दाम 50 पैसे प्रति किलो काम करते हैं, तो सीमेंट के दाम 5 रुपए प्रति बोरी बढ़ा दिए जाते हैं। इसे सरकार का कड़ा कदम कहते हैं। लोगों में चर्चा शुरू हो जाती है कि भाई, सरकार हो तो ऐसी। देखो दिल पर पत्थर रखकर कड़े कदम उठा रही है। आखिर हमारे लिए ही उठा रही है क्योंकि हमारी चिंता सरकार को है। सरकार हमें कड़वे फैसले के लिए तैयार हो जाने को कह रही है, तो हमें तैयार हो जाना चाहिए। जैसे हम सुबह नहा धोकर दफ्तर जाने के लिए, दुकान जाने के लिए, मित्रों से गपशप लगाने के लिए तैयार होकर जाते हैं, उसी तर्ज पर हमें सरकार के एक आह्वान पर कड़वे फैसले झेलने के लिए तैयार बर तैयार रहना चाहिए। सरकार कड़े कदम उठाने के लिए मजबूर है, लेकिन हमें मजबूत बने रहना चाहिए। एक अच्छे नागरिक की यही पहचान होती है।

IRDAI ने बताया पॉलिसीहोल्डर को उनके अधिकार, अब कंपनियां नहीं कर पाएंगी मनमानी

परिवहन विशेष न्यूज

बीमा धारक अधिकार कई बार पॉलिसी होल्डर पॉलिसी तो ले लेते हैं लेकिन वह अपने अधिकारों के बारे में नहीं जानते हैं। बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी IRDAI ने हाल ही में इसको लेकर मास्टर सर्कुलर जारी किया। इस सर्कुलर में इरडा ने पॉलिसीधारकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया। आइए इस आर्टिकल में विस्तार से जानते हैं।

नई दिल्ली। इंश्योरेंस धारकों को आसानी देने के लिए बीमा नियामक इरडा (IRDAI) द्वारा कई नियम जारी किये जाते हैं। अब इरडा ने पॉलिसी धारकों के लिए एक मास्टर सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में नियामक ने पॉलिसीधारकों को उनके अधिकारों के बारे में बताया है।

अगर आपके पास भी लाइफ इंश्योरेंस (Life Insurance) या हेल्थ इंश्योरेंस (Health Insurance) है तो आपको अपने अधिकारों के बारे में जान लेना चाहिए ताकि कोई इंश्योरेंस कंपनी (Insuance Company) अपनी मनमानी न कर पाएं। हम आपको इस आर्टिकल में पॉलिसीधारकों के अधिकारों के बारे में बताएंगे।

फिजिकल कॉपी

अगर आप ऑनलाइन इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपको ऑनलाइन सभी जानकारी मिल जाती है। लेकिन, अगर आप इंश्योरेंस की फिजिकल कॉपी लेना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से ले सकते हैं। इसके लिए कंपनी द्वारा मनाही नहीं की जाएगी। जी हां, कई बार पॉलिसीहोल्डर को लगता है कि उसनें ऑनलाइन पॉलिसी लिया है तो वह फिजिकल फॉर्मेट में कॉपी नहीं ले सकता है। लेकिन, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर पॉलिसीहोल्डर फिजिकल फॉर्मेट में कॉपी मांगता है तो इंश्योरेंस कंपनी उसे यह उपलब्ध करवाएगी। हालांकि, पॉलिसीधारक को इसके बारे में प्रपोजन फॉर्म में इसकी जानकारी देनी होगी कि वह फिजिकल फॉर्मेट में भी इंश्योरेंस की कॉपी चाहता है।

7 दिन के भीतर आंशिक निकासी

कई बार बीमा कंपनी यह कहती है कि आंशिक निकासी में काफी समय लगता है। जबकि ऐसा नहीं है। इरडा के नियमों के अनुसार अगर कस्टमर आंशिक निकासी करना चाहता है तो इंश्योरेंस कंपनी को इस काम के लिए केवल 7 कारोबारी दिन मिलते हैं। अगर 7 दिन से ज्यादा समय लगता है तो कंपनी को कस्टमर को बताना होगा कि आंशिक निकासी में देरी क्यों हो रही है।

इसके अलावा कंपनी जैसे ही प्रपोजल फॉर्म एक्सेप्ट करता है तो उसे उसके बाद पॉलिसी जारी करने में केवल 15 दिन का समय होता है। कंपनी कभी-भी प्रपोजल फॉर्म के साथ शुरुआती प्रीमियम नहीं ले सकती है। जब पॉलिसी जारी हो जाएगी उसके बाद ही कंपनी पॉलिसीहोल्डर से प्रीमियम ले सकती है।

कंपनी को पॉलिसी जारी होने के बाद कस्टमर को कुछ डॉक्यूमेंट देने होंगे। इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि पॉलिसी जारी होने के बाद वह पॉलिसीहोल्डर को कवरिंग लेटर, प्रपोजल फॉर्म की कॉपी, बेनिफिट इलस्ट्रेशन की कॉपी और सीआईएस यानी कस्टमर इन्फॉर्मेशन शीट उपलब्ध करवाएं।

वापस कर सकते हैं पॉलिसी

इरडा ने बताया कि पॉलिसीहोल्डर के पास 30 दिन का फ्री लुक पीरियड होता है। इसका मतलब है कि अगर किसी पॉलिसीधारक ने कोई पॉलिसी ली लेकिन बाद में उसे वह पॉलिसी पसंद नहीं आई तो वह इसे 30 दिन के भीतर वापस कर सकता है।

स्टील डंप के लिए चीन की कसी जाएगी लगाम? वाणिज्य मंत्री कर रहे तैयारी

परिवहन विशेष न्यूज

चीन स्टील बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी है। लेकिन वहां 2020 से डिमांड कमजोर है। चीन में प्रॉपर्टी संकट बढ़ने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। इससे स्टील का भाव कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अपने स्टील को सस्ते भाव में भारत जैसे देशों में डंप करने लगा। चीन में स्टील की डिमांड लंबे वक्त तक कमजोर बनी रहने वाली हैं।

नई दिल्ली। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को कहा कि उन्होंने इस्पात उद्योग को 'अनुचित' प्रतिस्पर्धा के बारे में चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया है, जिससे इस क्षेत्र की वृद्धि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उचित कदम उठाए जा सकें। स्टील इंडस्ट्री की कुछ कंपनियों ने चीन से कम कीमत के आयात पर चिंता जताई है।

गोयल ने कहा, 'मैंने इस्पात उद्योग को आमंत्रित किया है कि वे उस अनुचित प्रतिस्पर्धा को समझें जिसका उनमें से कुछ को सामना करना पड़ रहा है, तथा उचित कदम उठाएं ताकि इस्पात उद्योग जीवंत बना रहे, बढ़ता रहे तथा भारतीय अर्थव्यवस्था में रोजगार जोड़े।' उन्होंने बढ़ते आयात के खिलाफ समान अवसर प्रदान करके घरेलू उद्योग की रक्षा के लिए सीमा समायोजन कर लागू करने का विचार पांच सितंबर को पेश किया था।

गोयल ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे (आईएमईईसी) का उद्देश्य संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, जार्डन, इजरायल और यूरोपीय संघ (ईयू) के माध्यम से भारत, पश्चिम एशिया और यूरोप को जोड़ना है। उन्होंने कहा, "मुझे विश्वास है कि यह महत्वपूर्ण पहल भारत के समुद्र क्षेत्र की सुरक्षा को बढ़ाएगी और एक रणनीति के रूप में यह बहुत कम मार्गों पर हमारी निर्भरता को कम करेगी जो आज हमारी समुद्री सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकते हैं और इससे लॉजिस्टिक्स लागत कम करने में भी मदद मिलेगी।"

स्टील डंप क्यों कर रहा चीन

चीन स्टील बाजार का सबसे दिग्गज खिलाड़ी है। लेकिन, वहां 2020 से डिमांड कमजोर है। चीन में प्रॉपर्टी संकट बढ़ने से चीजें और भी ज्यादा खराब हो गई। इससे स्टील का भाव कई साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। ऐसे में अपने स्टील को सस्ते भाव में भारत जैसे देशों में डंप करने लगा। चीन की बड़ी स्टील कंपनियों का मानना है कि वहां स्टील की डिमांड लंबे वक्त तक कमजोर बनी रहने वाली हैं। भारत के स्टील निर्माता लगातार सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि चीन की स्टील डंपिंग पर लगाम लगाई जाए, क्योंकि इससे घरेलू उद्योग बर्बाद हो रहा है।

डिविडेंड से कैसे मिलता है डबल बेनेफिट, यहां समझें पूरी बात

शेयर बाजार में निवेश करने वाले निवेशक ने कभी न कभी डिविडेंड (Dividend) सुना होगा। बाजार में अक्सर निवेशक उन कंपनियों पर नजर बनाए रखते हैं जो डिविडेंड देती है। ऐसे में कई निवेशकों का सवाल होता है कि डिविडेंड से निवेशकों को कैसे लाभ होता है। आपको बता दें कि डिविडेंडे से एक नहीं बल्कि दो लाभ होता है यानी निवेशकों को डबल बेनिफिट मिलता है।

नई दिल्ली। शेयर बाजार के निवेशकों की नजर डिविडेंड पर रहती है। हालांकि, डिविडेंड एक तरह का रिवॉर्ड है जो कभी कभी कंपनी देती है। इसका मतलब है कि हर साल डिविडेंड (Dividend) मिले यह भी तय नहीं है लेकिन, फिर भी निवेशकों का फोकस डिविडेंड पर रहता है।

कई बार निवेशक यह भी कहते हैं कि डिविडेंड से लाभ हुआ है। ऐसे में सवाल आता है कि डिविडेंड से कैसे निवेशकों को डबल लाभ हो रहा है।

डिविडेंड क्या है?

कंपनी जब मुनाफे में होती है तो वह अपने शेयरधारकों को डिविडेंड देती है। यह डिविडेंड कैश, शेयर या फिर दूसरे रूप में हो सकता है। इससे एक बात तो समझ आ रहा है कि डिविडेंड से निवेशकों को लाभ होता है। शेयरहोल्डर्स को कितना डिविडेंड मिलेगा और यह डिविडेंड किस दिन शेयरधारकों के अकाउंट में आएगा यह कंपनी द्वारा तय किया जाता है।

उदाहरण के तौर पर 6 सितंबर को NBCC India के शेयरधारकों को डिविडेंड मिला है। हालांकि कंपनी ने डिविडेंड का एलान पहले ही कर दिया था पर शेयरधारक के अकाउंट में किस दिन डिविडेंड आएगा यह कंपनी ने तय किया। जिन कारोबारी सत्र में निवेशकों के अकाउंट में डिविडेंड आता है उस दिन कंपनी के शेयर एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड (EX-Dividend Trade) करते हैं।

डिविडेंड से कैसे होता है डबल फायदा

डिविडेंड से निवेशकों को एक लाभ नहीं होता है बल्कि निवेशकों को डबल लाभ होता है। इसे ऐसे समझिए कि अगर आपके पास किसी कंपनी के 5000 शेयर है और आपने हर स्टॉक खरीदने 400 रुपये यानी 5,000 शेयर के लिए 20 लाख रुपये का निवेश किया है। यह शेयर आपके पास 1 साल से है और 1 साल में शेयर 18 फीसदी का रिटर्न दिया। इसका मतलब है कि रिटर्न के जरिये आपको 3,60,000 रुपये का लाभ हुआ।

अब कंपनी हर शेयर पर 12 रुपये का डिविडेंड दे रही है। आपके पास 5,000 शेयर थे तो आपको 60,000 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। एक तरफ से आपको रिटर्न से 3,60,000 रुपये का फायदा हुआ और दूसरी तरफ से आपको डिविडेंड के जरिये 60,000 रुपये का लाभ हुआ। इस तरह डिविडेंड के जरिये आपको डबल फायदा हुआ।

निवेश के लिए कौन-सा इंडेक्स फंड रहेगा सही? किस आधार पर चुनें बेस्ट इंडेक्स फंड?

आज के समय में निवेश के कई ऑप्शन मौजूद है। इनमें से इंडेक्स फंड (Index Fund) भी काफी पॉपुलर हो गया है। इंडेक्स फंड के जरिये भी निवेशक को मुनाफा होता है। अगर आप भी इंडेक्स फंड में निवेश का सोच रहे हैं तो आपको बेस्ट इंडेक्स फंड सेलेक्ट करना चाहिए। हम इस आर्टिकल में बताएंगे कि बेस्ट इंडेक्स फंड के लिए किन पैरामीटर को ध्यान में रखें।

नई दिल्ली। निवेश के लिए निवेशक सबसे पहले यह देखता है कि कहां कम रिस्क है। इसके लिए वह कई ऑप्शन के बारे में रिसर्च भी करवाते हैं। अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो आप कन्फ्यूज रहते हैं कि आपको कौन-से इंडेक्स फंड में निवेश करना चाहिए।

सही इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने में कई बार निवेशकों को काफी परेशानी का सामना करन पड़ता है। दरअसल, इंडेक्स फंड को ट्रैक करने के लिए आज कई ऑप्शन हैं। ऐसे में सवाल है कि निवेशक को सही इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

इंडेक्स फंड सेलेक्ट करने से पहले आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखने की जरूरत है।

एक्सपेंस रेशियो

आपको यह जरूर देखना चाहिए कि आप जिस फंड में निवेश कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेश्यो कितना है। एक्सपेंस रेश्यो एक तरह का चार्ज है जो म्यूचुअल फंड हाउस इन्वेस्टर्स से लेता है। अगर कंपनी कम फीस लेती है तो इसका मतलब है कि निवेशकों को ज्यादा लाभ होने की संभावना है।

कम निवेश में ज्यादा रिटर्न

आपको उस फंड में निवेश करना चाहिए जिसमें कम खर्च हो यानी कम फीस लगे। कम खर्च वाले फंड में आपको रिटर्न से सही तरीके से फायदा होगा।

ट्रैकिंग एरर

जब इंडेक्स फंड और बेंचमार्क इंडेक्स के परफॉर्मेंस के बीच में अंतर होता है तो इसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। ऐसे में सही इंडेक्स फंड सेलेक्ट करते समय आपको यह देखना जरूर है कि किस फंड का ट्रैकिंग एरर कम है। जिस फंड का ट्रैकिंग एरर कम होता है आपको वह सेलेक्ट करना चाहिए। दरअसल, इससे पता चलता है कि फंड बेंचमार्क इंडेक्स को सही तरह से ट्रैक कर रहा है।

निवेश से पहले रखें ध्यान

- इंडेक्स फंड में उन निवेशकों को निवेश करना चाहिए जो शेयर बाजार से जुड़ी जटिलता से बचना चाहते हैं।
- इंडेक्स फंड एक स्पेशल इंडेक्स को ट्रैक करता है। ऐसे में निवेशक को शेयर बाजार के उतार-चढ़ाव की चिंता कम होती है।
- इस फंड में स्टॉक मार्केट की तुलना में जोखिम कम होता है। यह फंड पूरे इंडेक्स को डायवर्सिफाइड तरीके से ट्रैक करता है।
- इंडेक्स फंड का एक्सपेंस रेश्यो बाकी एक्टिव फंड की तुलना में कम होता है। कम एक्सपेंस रेश्यो होने की वजह से निवेशक को काफी अच्छा रिटर्न मिलता है।

निवेश के वक्त रहें सावधान

अगर आप इंडेक्स फंड में निवेश करने का सोच रहे हैं तो बता दें कि यह फंड भी उन निवेशकों के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। हालांकि, इस फंड में निवेशक पूरी तरह इक्विटी में निवेश करता है ऐसे में रिस्क भी रहता है। बाजार के उतार-चढ़ाव का असर फंड पर पड़ता है। ऐसे में इस फंड में उन निवेशकों को पैसा लगाना चाहिए जो रिस्क ले सकते हैं।

कहां निवेश करने पर मिलेगा बेहतर रिटर्न, यहां जानें सबकुछ

Flexi Cap vs Multi Cap vs ELSS निवेश में म्युचुअल फंड (Mutual Fund) काफी पॉपुलर ऑप्शन हो गया है। म्युचुअल फंड के निवेशकों की संख्या में लगातार तेजी देखने को मिली है। म्युचुअल फंड में भी निवेश करने के कई तरीके हैं। इन तरीकों में से तीन Flexi Cap Multi Cap और ELSS है। इन तीनों ऑप्शन में से किसमें बेहतर रिटर्न मिलेगा? आइए आर्टिकल में इसका जवाब जानते हैं।

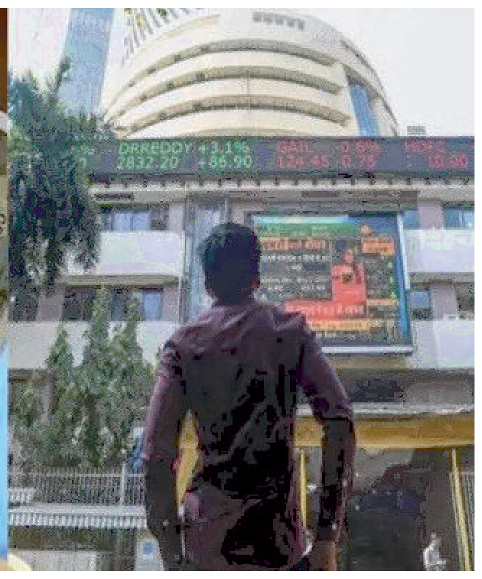

नई दिल्ली। इन्वेस्टमेंट के लिए मार्केट में कई ऑप्शन मौजूद हैं। निवेशक वेल्थ क्रिएशन के लिए रिस्क लेकर निवेश करते हैं। अगर बात निवेश ऑप्शन की करें तो मार्केट में Flexi Cap, Multi Cap और ELSS काफी पॉपुलर ऑप्शन में से एक हैं।

इन सभी ऑप्शन में निवेश करके कई निवेशकों को लाभ भी मिला है। लेकिन जो निवेशक अभी इन्वेस्टमेंट सेक्टर में नए हैं उनके मन में हमेशा सवाल रहता है कि इनमें से कौन-सा ऑप्शन उनके लिए बेस्ट रहने वाला है। आज हम आपको इन तीनों विकल्पों के अंतर को समझाने की कोशिश करेंगे।

वैसे बता दें कि अगर आप इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो के साथ प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो आपको फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप और इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) में से किसी एक में निवेश करना चाहिए।

मल्टी कैप फंड

म्युचुअल फंड में ही मल्टी कैप फंड (Multi Cap Fund) आता है। यह इक्विटी म्युचुअल फंड है। अब बात करें कि मल्टी कैप फंड क्या है तो इसके नाम से ही समझ गए हैं कि इसका पोर्टफोलियो काफी डायवर्ज रहता है। यानी निवेशक के फंड में लार्ज-कैप, मिड-कैप और स्मॉल-कैप तीनों सेगमेंट के शेयर है। निवेशक इन तीनों सेगमेंट में कम से कम 25 फीसदी तक का निवेश करता है।

इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी निवेशक को 1 लाख रुपये का निवेश करना है तो वह 1 लाख का 25 फीसदी यानी 25,000 रुपये लार्ज-कैप में , 25 हजार रुपये स्मॉल कैप में और 25,000 रुपये मिड-कैप में निवेश करता है। बाकी के 25,000 रुपये को वो अपने मन पसंद के किसी भी फंड में निवेश कर सकता है।

फ्लेक्सी कैप फंड

फ्लेक्सी कैप फंड (Flexi Cap Fund) भी इक्विटी म्यूचुअल फंड में ही आता है। इस फंड की खास बात यह है कि निवेशक या फंड मैनेजर को किस फंड में निवेश करना है यह उसका फैसला है। इसमें निवेश की कोई सीमा फिक्सड नहीं है। कोई सीमा न होने की वजह से निवेशक ग्रोथ की उम्मीद के हिसाब से निवेश कर सकता है।

उदाहरण के तौर पर अगर निवेशक 1लाख रुपये का निवेश करना चाहता है तो वह अपने हिसाब से लार्ज-कैप , मिड-कैप या स्मॉल-कैप में निवेश कर सकता है। यानी वो चाहे तो लार्ज कैप में 70,000 रुपये, मिड-कैप में 20,000 रुपये और स्मॉल कैप में 10,000 रुपये का निवेश कर सकता है। हालांकि, निवेश से पहले निवेशक को ग्रोथ को आंकलन कर लेना चाहिए।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम

मार्केट में इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम (ELSS) काफी पॉपुलर है। बाजार नियामक के अनुसार निवेशक को ELSS के तहत का कम से कम 85 फीसदी निवेश शेयर्स में करना होता है। हालांकि, इसमें भी किस सेगमेंट में कितना निवेश करना है इसका फैसला निवेशक ही लेता है।

ELSS के पॉपुलर होने के पीछे इसका बेनिफिट है। यह एक टैक्स सेविंग स्कीम (Tax Saving Scheme) है। इसमें आयकर अधिनियम 1961 के 80सी धारा के तहत निवेशक 1.5 लाख रुपये तक का टैक्स बचा सकते हैं। हालांकि, इस स्कीम में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। यानी निवेश के तीन साल तक निवेशक फंड से निकासी नहीं कर सकता है।

आपके लिए कौन-सा ऑप्शन है सही?

अगर आप पोर्टफोलियो में डायवर्जन चाहते हैं तब आप मल्टी कैप फंड में निवेश करने का सोच सकते हैं। वहीं, टैक्स सेविंग करना चाहते हैं तो ELSS काफी अच्छा विकल्प रहेगा। इसके अलावा आपको पता है कि किस समय किस सेगमेंट में निवेश करना चाहिए तो ऐसे में आप फ्लेक्सी कैप फंड में निवेश करने का विचार कर सकते हैं।

गणेश चतुर्थी पर जारी हुए पेट्रोल-डीजल के दाम, टंकी फुल कराने से पहले चेक करें कीमत

परिवहन विशेष न्यूज

आज देश में धूम-धाम से गणेश चतुर्थी मनाया जा रहा है। इस मौके पर तेल कंपनियों ने पेट्रोल-डीजल के दाम जारी कर दिये हैं। वैसे तो आज भी पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कोई चेंज नहीं हुआ है लेकिन सभी शहरों में अलग दाम है तो आपको लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। आइए जानते हैं कि आपके शहर में पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिल रहा है।

आज देशभर में गणेश चतुर्थी का त्योहार धूम-धाम से मनाया जा रहा है। इस मौके पर फ्यूल प्राइस अपडेट हो गए हैं। देश की मुख्य तेल कंपनी हर दिन सुबह पेट्रोल-डीजल के दाम अपडेट करती है। आज के लिए भी फ्यूल प्राइस अपडेट हो गए हैं। नए अपडेट के मुताबिक फ्यूल प्राइस में कोई बदलाव नहीं हुआ है।

चूंकि, पेट्रोल-डीजल के दाम रोज अपडेट होते हैं। ऐसे में गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही तेल भरवाना चाहिए। आइए, जानते हैं कि आज आपके शहर में 1 लीटर पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिल रहा है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार 7 सितंबर 2024 (शनिवार) को पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 7 September 2024)

सफलता की कहानी: कोई हुआ 11 बार फेल तो किसी ने अपने पति को खोने के बाद बनाया लक्ष्य; बने सैन्य अधिकारी

शनिवार को सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में 297 कैडेट अधिकारी शामिल हुए। यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) के परमेश्वर ड्रिल स्क्वायर में आयोजित पासिंग आउट परेड की समीक्षा उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने की। यहां किसी ने सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में 11 बार फेल होने के बाद मुकाम हालिल किया तो किसी ने पति को खोने के बाद पढ़ें संघर्षगाथा

चेन्नई। प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद जुनून और दृढ़ संकल्प से अपने सपने को साकार किया जा सकता है। शनिवार को सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में शामिल 297 कैडेट अधिकारियों की संघर्षगाथा इसी जिजीविषा को जीवंत कर रही है।

सैन्य वर्दी पहनने का सपना साकार हो गया

2020 में ट्रेन हादसे में अपने पति कैप्टन जगतार सिंह को खोने वाली ऊषा रानी का सैन्य वर्दी पहनने का सपना साकार हो गया। उनके साथ ही इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रानिक्स इंजीनियर जिग्मित रिंगजिन, आडिटर फाल्के निशांत बालासाहेब और मुंबई की भीड़भाड़ वाली चाल में पले-बढ़े भावसार जयेश का सेना में शामिल होने का सपना आज राष्ट्रप्रहरी के रूप में जीवंत हो उठा है। वह सेवा चयन बोर्ड की परीक्षा में 11 बार फेल हुए थे। इसके बावजूद हार नहीं मानी। उनको अपने परिवार के भरण-पोषण के लिए ऑनलाइन गणित शिक्षक और जिम प्रशिक्षक के रूप में भी काम करना पड़ा। अब सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा करेंगे।

शनिवार को सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में 297 कैडेट अधिकारी शामिल हुए। इनमें 39 महिला कैडेट अधिकारी भी हैं। यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) के परमेश्वर ड्रिल स्क्वायर में आयोजित पासिंग आउट परेड की समीक्षा उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने की।

पति की मौत से टूटने वाली ऊषा रानी ने बनाया लक्ष्य

ओटीए ने कहा कि मित्र देशों के दस कैडेट अधिकारी और पांच महिला कैडेट अधिकारियों ने भी सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया। इस अवसर पर सेना में शामिल होने वाले कई अधिकारियों के संघर्ष की कहानी सामने आई है। ट्रेन हादसे में अपने पति की मौत से टूटने वाली ऊषा रानी ने इससे उबरने के लिए सेना में शामिल होने का रास्ता चुना। एक बयान में बताया गया, ''संयोगवश वह उसी सेवा चयन बोर्ड में शामिल हुईं, जहां उनके पति चुने गए थे। वह शादी की वर्षगांठ के दिन ओटीए में शामिल हुईं।''

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया

हिमाचल के किन्नौर जिले के जिग्मित रिंगजिन ने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में नौकरी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। वह सातवें प्रयास में सफल हुए और अक्टूबर, 2023 में ओटीए में शामिल हुए। जबकि फाल्के सीआरपीएफ में हेड कांस्टेबल के बेटे हैं। उनके पिता की मृत्यु लाइलाज बीमारी के चलते हो गई थी। वह अपनी मां और छोटी बहन की देखभाल की जिम्मेदारी संभालने के साथ ही अपने सपने को साकार किया।

चीन व पाकिस्तान दोनों सीमाओं पर सेना मजबूत

उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि भारतीय सेना नए खतरों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती है। सेना पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर मजबूत है। उन्होंने यह बात शनिवार को यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में पा¨सग आउट परेड से इतर कही। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, ''भारतीय सेना हमेशा नए खतरों के लिए तैयार है। पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से लगती सीमाओं पर हम मजबूत हैं। भारतीय सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है।''

अब पाकिस्‍तान और चीन की खैर नहीं! भारतीय सेना में शामिल हुए 297 कैडेट अधिकारी

उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि भारतीय सेना नए खतरों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती है। सेना पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर मजबूत है। उन्होंने यह बात शनिवार को यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में पासिंग आउट परेड से इतर कही। 39 महिला कैडेट अधिकारियों समेत 297 कैडेट अधिकारियों को सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में शामिल किया गया।

चेन्नई। उप सेना प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा कि भारतीय सेना नए खतरों का सामना करने के लिए सदैव तैयार रहती है। सेना पाकिस्तान और चीन दोनों सीमाओं पर मजबूत है। उन्होंने यह बात शनिवार को यहां अधिकारी प्रशिक्षण अकादमी (ओटीए) में पासिंग आउट परेड से इतर कही। इस समारोह में 39 महिला कैडेट अधिकारियों समेत 297 कैडेट अधिकारियों को सेना की विभिन्न इकाइयों और सेवाओं में शामिल किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने कहा, 'भारतीय सेना हमेशा नए खतरों के लिए तैयार है।' पाकिस्तान और चीन दोनों देशों से लगती सीमाओं पर हम मजबूत हैं। भारतीय सेना किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है।'

महिला कैडेट अधिकारियों ने पूरा किया प्रशिक्षण

ओटीए के परमेश्वर ड्रिल स्क्वायर में आयोजित पासिंग आउट परेड की समीक्षा लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि ने की। ओटीए ने कहा कि मित्र देशों के दस कैडेट अधिकारी और पांच महिला कैडेट अधिकारियों ने भी सफलतापूर्वक अपना प्रशिक्षण पूरा किया।

'सैनिक आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं'

मित्र देशों के कैडेट के प्रशिक्षण प्राप्त करने से अंतरराष्ट्रीय सीमाओं पर सौहार्द और सहयोग की भावना को बढ़ावा मिला है। इस मौके पर उप सेना प्रमुख ने अपने संबोधन में कैडेट अधिकारियों और ओटीए कर्मियों की अनुकरणीय उपलब्धियों के लिए सराहना की। उन्होंने कहा, 'आपको जल्द ही दुनिया के कुछ बेहतरीन सैनिकों की कमान संभालने का अवसर प्राप्त होगा। ये सैनिक आपकी सबसे मूल्यवान संपत्ति हैं। इसलिए अपनी कमान को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कुशल, अनुशासित और धैर्यवान बनाएं।'

असम में बिना एनआरसी नहीं बनेगा आधार कार्ड, CM हिमंत का बड़ा फैसला

परिवहन विशेष न्यूज

एनआरसी पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि अब राज्य में नया आधार कार्ड बनाने के लिए एनआरसी आवेदन रसीद नंबर अनिवार्य होगा। इसके बिना आधार कार्ड नहीं बनाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि इस पर एक विस्तृत एसओपी तैयार की जाएगी और बताया कि ये नियम कब से लागू होगा।

गुवाहाटी। असम में अब बिना एनआरसी के आधार कार्ड नहीं बनेगा। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने शनिवार को कहा कि असम में आधार कार्ड के लिए सभी नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर (एआरएन) जमा करना होगा। एक विस्तृत एसओपी तैयार की जाएगी और इसे एक अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) की आवेदन रसीद संख्या जमा करने से अवैध विदेशियों पर रोक लगेगी। मुख्यमंत्री ने कहा, 'आधार कार्ड के लिए आवेदन जनसंख्या से अधिक हैं। हमने फैसला किया है कि नए आवेदकों को अपना एनआरसी आवेदन रसीद नंबर जमा करना होगा।'

इन पर नहीं होगा लागू

उन्होंने कहा, 'असम में आधार प्राप्त करना आसान नहीं होगा और उम्मीद है कि अन्य राज्य भी आधार कार्ड जारी करने में सख्ती बरतेंगे।' सरमा ने कहा कि एआरएन जमा करना उन 9.55 लाख लोगों पर लागू नहीं होगा, जिनकी बायोमीट्रिक पहचान एनआरसी प्रक्रिया के दौरान लॉक हो गए थे। उन्हें उनके कार्ड मिलेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि चार जिलों ने उनकी कुल अनुमानित जनसंख्या की तुलना में आधार कार्ड के लिए अधिक आवेदन की सूचना दी है। ये जिले बारपेटा, धुबरी, मोरीगांव और नागांव हैं। वहीं, सरमा ने शनिवार को कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो राज्य सरकार सामने आए अवैध ऑनलाइन ट्रेडिंग घोटाले की सीबीआई जांच की सिफारिश करेगी।

'कम हुई उग्रवाद संबंधित घटनाएं'

इसे लेकर अब तक 59 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में उग्रवाद संबंधित घटनाएं कम हुई हैं। उन्होंने असम में पुलिस स्टेशनों को और अधिक जन-केंद्रित बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया।

देश के हाईकोर्टों में लंबित 62 हजार से अधिक मामले, इनमें से तीन 72 साल पुराने

विभिन्न हाई कोर्टों में लगभग 62 हजार ऐसे मामले लंबित हैं जो 30 साल से अधिक पुराने हैं और इनमें से तीन मामले 1952 से ही निपटारे की प्रतीक्षा में हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार हाई कोर्टों में चार मामले 1954 से और नौ मामले 1955 से लंबित हैं। 1952 से लंबित तीन मामलों में से दो कलकत्ता हाई कोर्ट और एक मद्रास हाई कोर्ट का है।

परिवहन विशेष न्यूज

नई दिल्ली: विभिन्न हाई कोर्टों में लगभग 62 हजार ऐसे मामले लंबित हैं, जो 30 साल से अधिक पुराने हैं और इनमें से तीन मामले 1952 से ही निपटारे की प्रतीक्षा में हैं। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, हाई कोर्टों में चार मामले 1954 से और नौ मामले 1955 से लंबित हैं। 1952 से लंबित तीन मामलों में से दो कलकत्ता हाई कोर्ट और एक मद्रास हाई कोर्ट का है।

जिला अदालतों, हाई कोर्टों और सुप्रीम कोर्ट समेत विभिन्न अदालतों में पांच करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। इस हफ्ते की शुरुआत में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने न्यायपालिका में ''स्थगन मांगने की संस्कृति'' में बदलाव का आह्वान किया था।

हाई कोर्टों में लगभग 2.45 लाख मामले लंबित

उन्होंने कहा था कि लंबे समय से लंबित मामले न्यायपालिका के समक्ष एक बड़ी चुनौती हैं। सभी पक्षकारों को इस समस्या को प्राथमिकता देकर इसका समाधान ढूंढना होगा। राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड (एनजेडीजी) के अनुसार, हाई कोर्टों में लगभग 2.45 लाख मामले लंबित हैं, जो 20 से 30 साल पुराने हैं।

कानून मंत्री ने किया धारणा को तोड़ने का एलान

इसी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस धारणा को तोड़ने का आह्वान किया था कि भारतीय अदालतें तारीख पर तारीख संस्कृति का पालन करती हैं। लंबित मामलों के विश्लेषण से पता चलता है कि मुकदमेबाजी में शामिल पक्ष या तो उपस्थित नहीं होते हैं या मामले को आगे बढ़ाने में रुचि नहीं रखते हैं। ऐसे 25 से 30 प्रतिशत मामलों को एक बार में ही बंद किया जा सकता है।

सांसद मानस रंजन मंगराज ने सुजीत को आस्था का हत्यारा बताया

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: पूर्व राज्यसभा सांसद सुजीत कुमार की पार्टी नीति पर तीखी प्रतिक्रिया हुई है। इस बीच सांसद मानस रंजन मंगराज ने सोशल मीडिया 'एक्स' पर अपनी चिंता जाहिर की है। सांसद मानस रंजन मंगराज ने सुजीत को आस्था का हत्यारा बताया। मानस नगराज ने कहा कि जिस पार्टी ने आपको हमेशा सम्मान दिया, पुरस्कृत किया, उस पर आपका विश्वास घातक है।आपके फैसले ने कालाहांडी के लोगों को चौंका दिया है। सांसद मानस मंगराज ने कहा, हम हमेशा नवीन और बीजेडी के साथ खड़े हैं। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए शुक्रवार को बीजेडी से निकाले जाने के कुछ ही घंटों के भीतर सुजीत कुमार भाजपा में शामिल हो गए।

ओड़िशा में एक और 'बंदेभारत एक्सप्रेस' ट्रेन उपलब्ध होगी। यह ट्रेन ब्रह्मपुर-टाटानगर के बीच चलेगी

मनोरंजन सासमल, स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेस्वर्: ओड़िशा में एक और 'बंदेभारत एक्सप्रेस' ट्रेन उपलब्ध होगी। यह ट्रेन ब्रह्मपुर-टाटानगर के बीच चलेगी। इस ट्रेन का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने कीच योजना बना रहे हैं। इस ट्रेन के साथ ओडिशा में कुल 4 'बंदेभारत एक्सप्रेस' चलेंगी।आठ सितंबर को टाटानगर से ब्रह्मपुर रूट पर बंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन का ट्रायल करने का निर्णय लिया गया है। टाटानगर से ब्रह्मपुर के बीच चलने वाली बंदेभारत एक्सप्रेस ट्रेन 586 किमी की दूरी 7-8 घंटे में तय करेगी। इस रूट पर ट्रेन राजखरसुमन, चौबास, डांगवापोशी, बाशनपानी, क्योंझरगढ़, हरिचंद्रपुर, सुकिंदा रोड, झनकपुरा, कटक, भुवनेश्वर, खुर्दा रोड स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। हालांकि, जानकारी दी गई है कि इस ट्रेन का शेड्यूल जल्द ही रेलवे बोर्ड द्वारा जारी किया जाएगा।

कोंकण रेलवे लाइन पर टला बड़ा हादसा, ट्रैकमैन ने किया कमाल; इस तरह बचाई सैकड़ों यात्रियों की जान

ट्रैकमैन की सूझबूझ से कुमता और होन्नावर के बीच कोंकण रेलवे लाइन पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना शुक्रवार तड़के करीब 4.50 बजे हुई। ट्रैकमैन महादेव अपनी ड्यूटी पर थे। उनकी नजर ट्रैक ज्वाइंट की अधूरी वेल्डिंग पर पड़ी। उस समय तिरुअनंतपुरम-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इस मार्ग पर आ रही थी। एक्सप्रेस पहले ही स्टेशन से निकल चुकी थी और इस ओर तेजी से बढ़ रही थी।

कारवार: ट्रैकमैन की सूझबूझ से कुमता और होन्नावर के बीच कोंकण रेलवे लाइन पर एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घटना शुक्रवार तड़के करीब 4.50 बजे हुई। ट्रैकमैन महादेव अपनी ड्यूटी पर थे। उनकी नजर ट्रैक ज्वाइंट की अधूरी वे¨ल्डग पर पड़ी। उस समय, तिरुअनंतपुरम-दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस इस मार्ग पर आ रही थी। खतरे को भांपते हुए महादेव ने ट्रेन रोकने के लिए कुमटा स्टेशन से संपर्क किया।

हालांकि, एक्सप्रेस पहले ही स्टेशन से निकल चुकी थी और इस ओर तेजी से बढ़ रही थी। महादेव ने लोको पायलट से सीधे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन संपर्क स्थापित नहीं हो सका।उन्होंने बिना एक पल गंवाए निर्णय लिया।

लाल झंडी दिखाकर टाल दिया गया आपदा

वह पटरियों पर तेजी से दौड़ने लगे और पांच मिनट में आधा किलोमीटर की दूरी तय कर ली। उन्होंने ऐन वक्त पर लाल झंडी दिखाकर संभावित आपदा को टाल दिया। वेल्डिंग का काम पूरा होने के बाद राजधानी एक्सप्रेस सुरक्षित रूप से कारवार की ओर अपनी यात्रा फिर से शुरू कर दी। सैकड़ों यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने वाले महादेव के त्वरित कार्यों की व्यापक रूप से प्रशंसा की गई।

नायक के रूप में सम्मानित हुए महादेव

कोंकण रेलवे जोन के अधिकारियों ने महादेव को एक नायक के रूप में सम्मानित किया। उनकी बहादुरी के लिए कोंकण रेलवे के सीएमडी ने उन्हें नकद पुरस्कार दिया।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023